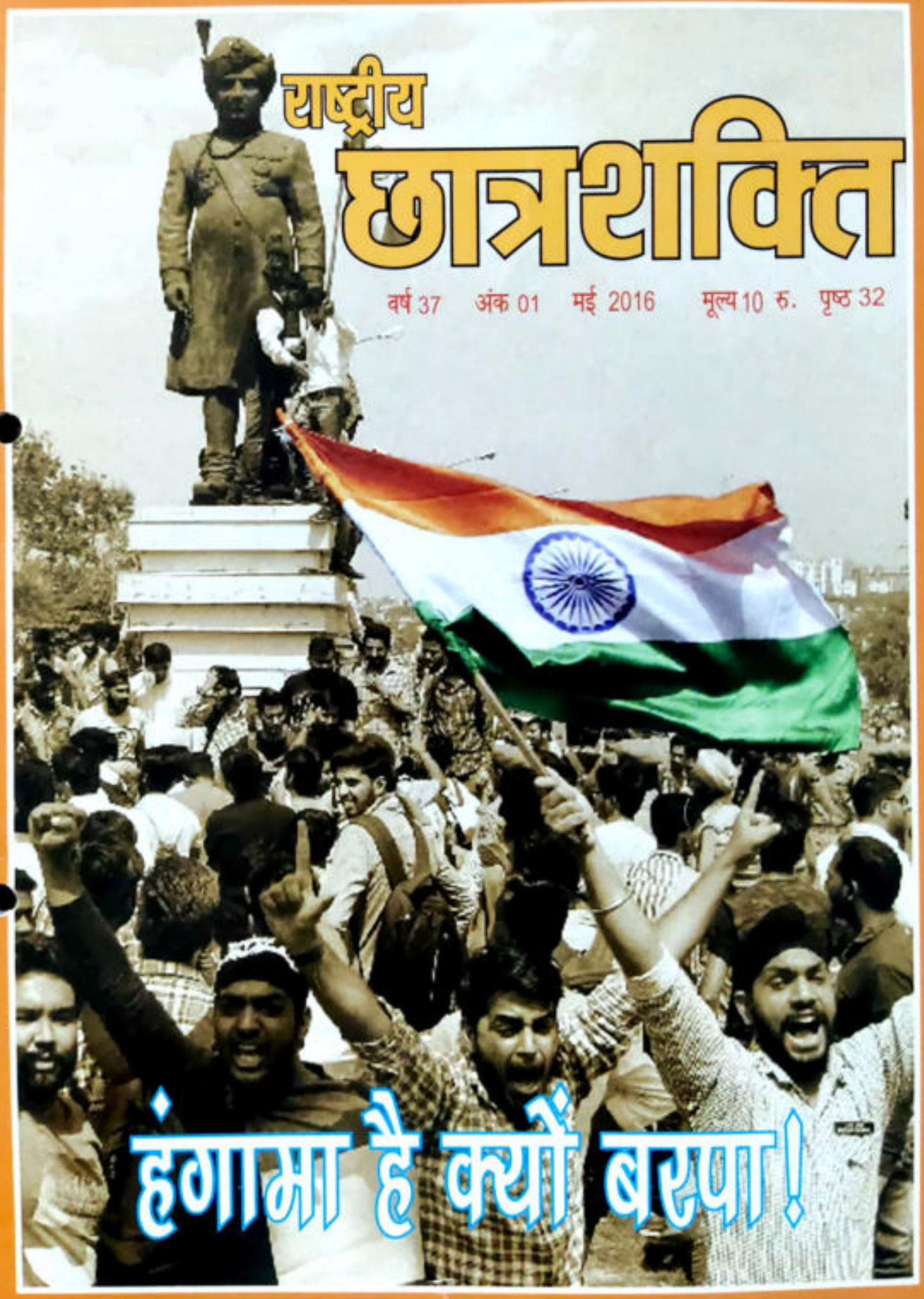

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 37 अंक 01 मई 2016 मूल्य 10 रु. पृष्ठ 32

हंगामा है क्यों बरपा!

उज्जैन में पर्यावरण महाकुंभ का उद्घाटन करते स्वामी चिदानन्द, सुनील आंबेकर व अन्य अतिथिगण

भुवनेश्वर में भीमराव अंबेडकर जयन्ती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते अभाविप कार्यकर्ता

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

संपादक मण्डल

आशुतोष

संजीव कुमार सिन्हा

अवनीश सिंह

अभिषेक रंजन

फोन : 011-23216298

ई-मेल : chhatrashakti.abvp@gmail.com

ब्लॉग :chhatrashaktiabvp.com

वेबसाईट :www.abvp.org

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए राजकुमार शर्मा द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट नई दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग को. 132, एफ. आई. ई. पटपड़गंज इंडस्ट्रीयल एरिया नई दिल्ली-92 से मुद्रित।

अनुक्रमणिका

विषय	पृ. सं.
सम्पादकीय	4
एनआईटी परिसर में मनेंगे राष्ट्रीय त्यौहार	5
उमर, अनिर्बान प्रतिबंधित, कन्हैया कुमार पर दस हजार का जुर्माना	9
देशभक्ति अपराध है तो बार-बार करूंगा : सौरभ शर्मा	10
सिर्फ अनिश्चितता ही निश्चित है –प्रखर जैन	11
उजागर हुआ वामपंथ का छद्म चेहरा	12
सिद्धांतनिष्ठ बलराज मधोक – संजीव सिन्हा	13
अभाविप का महाअभियान, समाज जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर होगा सर्वेक्षण	14
गरीबी एवं मेधावी छात्रों के हित में फैसला –श्रीरंग कुलकर्णी	16
अभाविप ने नई शिक्षा नीति पर स्मृति ईरानी को दिए सुझाव	18
सामाजिक समरसता के प्रतीक थे बाबा साहब : जी. लक्ष्मण	19
मूल्य आधारित हो नई शिक्षा नीति	21
कश्मीर घाटी में खेल	23
पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ संपन्न हुआ पर्यावरण महाकुंभ	25
कलम और कैमरे की कवायद – अवनीश सिंह राजपूत	27
वर्तमान सत्र से लागू हो नीट : विनय बिदरे	30

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

मानव जीवन का लक्ष्य है ईश्वर को जानना, उसे पाना और अंततः स्वयं ईश्वर हो जाना। नर से नारायण तक की यह यात्रा एक निरंतर यात्रा है। अपना यह लौकिक जीवन इसके एक अध्याय के रूप में समानान्तर चलता है। लौकिक यात्रा जब इस अनंत यात्रा के साथ तादात्म्य बनाते हुए चलती है तभी जीवन की सार्थकता है। लेकिन पश्चिम के जिन संस्कारों का प्रभाव भारतीय जनमानस पर आज सिर चढ़ कर बोल रहा है, उसमें जीवन की सार्थकता से ज्यादामोल सांसारिक सफलता का है। और यह सफलता मापी जाती है उस आय से, जो एक व्यक्ति बाजारवादी व्यवस्था में रहते हुए अर्जित करता है। यही कारण है कि एक प्रसिद्ध साहित्यकार एक जगह लिखते हैं - 'सफलता मनुष्य की नहीं, शैतान की कसौटी है।'

इस बाजार आधारित सफलता पाने के प्रयास में व्यक्ति जो इच्छित कामनाएं पूरी करने से चूक जाता है, उसे अपनी संतानों द्वारा पूरे होते देखना चाहता है। इसी के परिणामस्वरूप वह संतान के जन्म के साथ ही उसके भविष्य की दिशा भी निर्धारित कर देता है जिसके अनुकूल परिणाम देने के लिये वह संतान एक प्रकार से अभिशप्त होती है।

यहां किसी व्यक्ति की आत्मिक यात्रा की दिशा गौण हो जाती है, देवत्व की ओर बढ़ने की उसकी गति ठहर जाती है, रह जाती है एक प्रतियोगिता जिसमें अपने-आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की जिम्मेदारी उस किशोर मन पर थोप दी जाती है।

अपने प्रारब्ध को नकारने के प्रयास और प्रकृति के नित-नये खुलते पृष्ठों की सपनीली दुनियां से नजरें चुरा कर इस अप्राकृतिक, अमानवीय और अवांछनीय प्रतियोगिता का हिस्सा बनने के लिये विवश किये गये अनेक किशोर या तो विद्रोह कर बैठते हैं अथवा पलायन। विद्रोह उन्हें हिंसा की ओर धकेलता है तो पलायन का सबसे दुखद पहलू होता है आत्महत्या। यदि शिक्षा पूर्णत्व की प्राप्ति के स्थान पर आत्महत्या की ओर प्रेरित करे तो यह उसके लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति और व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है।

हाल ही में कोटा में विद्यार्थियों द्वारा प्रतियोगिता के दवाब में की जा रही आत्महत्या की रपट झकझोर देने वाली है। माता-पिता की आकांक्षाओं की बलि चढ़े यह युवा देश और समाज की अमूल्य सम्पदा सिद्ध हो सकते थे यदि उन्हें अपनी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार विकसित होने का अवसर दिया गया होता। माता-पिता की अधूरी आकांक्षाएं किशोर मानस के विरुद्ध संस्थागत रुप ले चुके इस दुष्चक्र का एक पहलू है। स्तरहीन शिक्षा देकर लाखों-करोड़ों के वारे-न्यारे करने वाले निजी शिक्षा संस्थान इस विभीषिका को बढ़ाने के लिये कम उत्तरदायी नहीं हैं। भ्रष्टाचार तो इसका एक अभिन्न अंग है ही। इसके अतिरिक्त नीतिगत स्तर पर जवाबदेही का न होना और समग्र राष्ट्रीय नीति का अभाव भी महत्वपूर्ण कारक हैं।

हर व्यक्ति आवश्यक है और हर जीवन महत्वपूर्ण। साथ ही देश का भविष्य भी। भ्रमित, दिशाहीन और निराश युवा राष्ट्रनिर्माण में अपेक्षित भूमिका नही निभा सकते। वहीं, युवाओं की ऊर्जा और क्षमता के नियोजन की योजना के अभाव के चलते देश भी लाभान्वित होने से वंचित रहता है। दोनों का समन्वय ही देश के विकास की कुंजी है।

यह प्रसन्नता का विषय है कि केन्द्र सरकार ने नयी शिक्षा नीति के रूप में एक सकारात्मक पहल की है और अभाविप ने सदैव की भांति अपना रचनात्मक योगदान सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इससे पहले 80 के दशक में स्व. राजीव गांधी द्वारा लाई गयी शिक्षा नीति में भी परिषद ने अपने सुझाव दिये गये थे जिनमें से बड़ी संख्या में उक्त नीति में शामिल किये गये थे।

एक बार पुनः यह अवसर आया है तो अभाविप का स्पष्ट मत है कि भविष्य के भारत का चित्र सामने रख कर नीतियों का निर्धारण हो तथा देश के छात्र-युवा राष्ट्रनिर्माण की दिशा में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकें।

एनआईटी परिसर में मनेंगे राष्ट्रीय त्यौहार

छात्रों की मांगों के आगे झुका एनआईटी प्रशासन

नई दिल्ली। अच्छी शिक्षा और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे कश्मीर एनआईटी के छात्रों को थोड़ी राहत मिली है। छात्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए एनआईटी प्रशासन ने कुछ बातों पर त्वरित सहमति जता दी है। इस स्वीकृति के बाद डरे–सहमे कश्मीर से दिल्ली आये छात्रों के चेहरे पर खुशी दिख रही है। वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने भी एनआईटी के इस फैसले का स्वागत किया है। विद्यार्थी परिषद् के पदाधिकारियों ने एनआईटी श्रीनगर के छात्रों को संघर्ष के पथ पर मिली पहली जीत पर बधाई दी है।

एनआईटी श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर) के राष्ट्रवादी छात्रों के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् निरंतर खड़ी है। ऐसे में अभाविप के समर्थन के साथ खड़े इस छात्र आंदोलन की ही ताकत थी कि एनआईटी के निदेशक को दिल्ली आकर छात्रों से वार्ता करने पर विवश होना पड़ा। एनआईटी प्रशासन द्वारा जिन मांगों को स्वीकृति दी गयी है उसमें फैक्ट फाइंडिग कमेटी का पुनर्गठन, निश्चित अवधि निर्धारण, छात्र परिषद् की स्थापना, परीक्षा का बाह्य–मूल्यांकन एवं छात्रों के उपचार का खर्च वहन करना शामिल है। साथ ही कैंपस में छह महीने में दो बार स्वास्थ्य जांच कैंप लगाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

तीन–चार महीनों के अंदर मेडिकल सुविधाओं में वृद्धि, 80 कमरों वाले दो छात्रावासों तथा 15 कक्षाओं को छह महीने के अंदर पूरा करना, मेडिकल बिल दावों का भुगतान, परिसर में भोजन तथा फलों के स्टाल की मांगों पर भी संस्थान प्रशासन सहमत हो गया है। इस बीच यह भी फैसला किया गया कि परिसर में सभी राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाएंगे। इसके अलावा, छात्रवासों की विभिन्न समस्याओं पर शीघ्र कार्यवाही किये जाने, परिसर विस्तार पर कार्य होने के साथ कैंपस में छात्रों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए एक अलग कमेटी बनाये जाने पर भी जल्द फैसले लिए जाने का आश्वासन दिया गया।

एनआईटी श्रीनगर के रजिस्ट्रार फैयाज अहमद मीर का कहना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम और एनआईटी श्रीनगर के संचालक मंडल के साथ छात्रों की मुलाकात के बाद कई मांगों को कार्यान्वित करने के औपचारिक आदेश दे दिए गए हैं। सिर्फ एनआईटी श्रीनगर परिसर को स्थानांतरित करने की गैरवाजिब मांग को छोड़कर।

परिसर स्थानांतरण की मांग को लेकर प्रदर्शन

नई दिल्ली। एनआईटी के छात्रों ने श्रीनगर से परिसर को किसी दूसरे जगह स्थानांतरित करने की मांग को लेकर दिल्ली स्थित जंतर–मंतर पर प्रदर्शन किया था। उनका कहना था कि छात्रों की सुरक्षा को लेकर सरकार जल्द फैसला करें।

विरोध प्रदर्शन करने वाले एक छात्र ने कहा, 'हम चाहते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय हमारी मांगों पर ध्यान दे और एनआईटी परिसर को श्रीनगर से किसी दूसरे जगह स्थानांतरित करे। इसके साथ ही छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर जवाबदेही तय की जाए।'

एक अन्य छात्र ने कहा कि हम चाहते हैं कि एनआईटी में गैर कश्मीरी छात्रों के खिलाफ दर्ज किये गए सभी मामले वापस लिये जाएं और सभी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए।

उल्लेखनीय है कि टी20 मैच के दौरान वेस्टइंडीज के हाथों भारत की पराजय के बाद कुछ स्थानीय छात्रों द्वारा खुशी प्रकट किये जाने और पटाखे फोड़े जाने का बाहर के छात्रों ने विरोध किया और इसके कारण संघर्ष हुआ था।

एक ओर जहां छात्रों में कुछ मांगों के माने जाने पर खुशी है वहीं उनका कहना है कि अभी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ है बल्कि यह शुरुआती सफलता मात्र है। छात्रों की माने तो एनआईटी श्रीनगर में पढ़ रहे समस्त छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। परिसर में किसी प्रकार की देशद्रोही गतिविधियां ना हो इसके लिए एनआईटी प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे.. ताकि छात्र बिना किसी भय के अपने शिक्षण कार्य पर ध्यान दे सकें।

बतादें कि बीते 19 अप्रैल को एनआईटी छात्रों और अभाविप पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एनआईटी श्रीनगर के संचालक डॉ रजत गुप्ता के साथ मुलाकात की थी। जिसमें शिक्षण के तरीकों, अकादमिक समस्याओं और सुरक्षा को लेकर छात्रों ने अपनी बात रखी थी। साथ ही, छात्रों के एक दल ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के समक्ष भी अपनी मांगों को रखा था। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री और एनआईटी निदेशकों ने छात्रों की मांगों पर गौर करते हुए फैसले किए।

वर्षभर में सवा लाख सदस्य बनाएगी अभाविप

मऊ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत की समीक्षा बैठक भीटी शिवजी मठ स्थित राम स्वरूप भारती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आयोजित हुई। इसमें गत वर्ष के कार्यों की समीक्षा करते हुए वर्ष 2016–17 की विस्तृत कार्य योजना बनी। इसके तहत गोरक्ष प्रांत में 50 हजार छात्राओं को संगठन से जोड़ने का लक्ष्य बनाया गया।

गोरक्ष प्रांत के मंत्री राकेश मौर्य ने कहा कि परिषद ने 400 इंटर कालेज व 200 महाविद्यालयों में अपनी कार्यकारिणी बनाने का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष कुल सवा लाख सदस्य बनाए जाएंगे। कहा कि शैक्षिक गुणवत्ता के निरंतर ह्रास पर शैक्षिक वर्ष में आंदोलन की योजना बनी है। छात्राओं को संगठन में सहभाग बढ़ाने के लिए प्रांतीय स्तर पर प्रतिभावना छात्रा सम्मेलन करने की योजना बनी है।

प्रशिक्षण एवं प्रकाशन प्रमुख मनोजकांत ने कहा कि कार्य विस्तार के लिए सिंहावलोकन जरुरी है। इसी लिए विद्यार्थी परिषद हर वर्ष मई माह में समीक्षा योजना बैठक करती है। इसमें गत वर्ष के लिए गए लक्ष्यों का आंकलन कर नई कार्ययोजना बनाई जाती है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कार्यकर्ता पूर्ण मनोस्थिति से काम करता और लक्ष्य तक पहुंचता है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डा. धर्मेंद्र सिंह ने चुनाव पर जोर देते हुए कहा कि इस वर्ष सभी कालेजों में छात्र संघ चुनाव होने की संभावना है। चुनाव को गंभीरता को लेते हुए अभी से लगना होगा।

जानिये क्या हुआ एनआईटी में...

एनआईटी श्रीनगर एक अप्रैल से ही विवाद के घेरे में है, जब टी–20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के हाथों गयी। इसके बाद स्थानीय तथा अन्य राज्यों के छात्रों के बीच झड़प हो गयी। पांच अप्रैल को स्थिति और बिगड़ गयी जब छात्रों के एक बड़े समूह ने तिरंगा मार्च निकालने का प्रयास किया और पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद मार्च का विरोध कर रहे उपद्रवी छात्रों ने जमकर हिंसा फैलाई और तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं इस पूरे घटनाक्रम में स्थानीय पुलिस की भूमिका भी उपद्रवी छात्रों के पक्ष में रही। पुलिस ने पूरे परिसर में मार्च निकाल रहे छात्रों को जमकर पीटा। घटना से डरे छात्र अपने घरों को वापस चले गये। घटना के एक पखवारा बीतने के बाद जब स्थिति सामान्य नहीं हुई तो डरे–सहमें छात्रों ने 19 अप्रैल को मानव संसाधन विकास मन्त्री स्मृति ईरानी के नाम एक पत्र अधिकारियों को सौंपा। इसमें छात्रों ने लिखा था, "हमारा अनुरोध है कि सम्मानित मानव संसाधन विकास मंत्री अथवा भारत के प्रधानमंत्री एनआईटी श्रीनगर के छात्रों के साथ आएं और हमारी सुरक्षा और शिक्षा की गारंटी लें। इसके साथ ही परिसर में सबसे ऊंची जगह पर बड़े आकार का तिरंगा फहराया जाये। इससे छात्रों में सुरक्षा का भाव आएगा और यह संदेश मजबूत होगा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और छात्रों को परिसर में और उसके बाहर राष्ट्र विरोधी तत्वों पर मनोवैज्ञानिक जीत हासिल होगी।"

श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) में 31 मार्च से कश्मीरी और ग़ैर कश्मीरी छात्रों के बीच हुई झड़प की घटना क्रम पर एक नजर....

31 मार्च – वेस्टइंडीज़ के हाथों भारत को मिली हार पर कश्मीरी छात्रों ने जश्न मनाया। नाराज ग़ैरकश्मीरी छात्रों ने भी 'भारत माता की जय' के नारे लगाए।

1 अप्रैल – मामले ने तूल पकड़ा और कई ग़ैर कश्मीरी छात्रों ने राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त कश्मीरी छात्रों के ख़लिाफ़ प्रदर्शन और नारेबाज़ी की। दोनों छात्र गुटों के बीच झड़प हुई और पुलिस ने आंसू गैस छोड़ा और लाठीचार्ज किया। जिसके बाद एनआईटी को बंद कर दिया गया।

4 अप्रैल – चार दिन बाद एनआईटी में शिक्षण कार्य शुरू हुआ, लेकिन कश्मीरी छात्रों द्वारा खुलेआम धमकी और प्रशासन द्वारा दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग़ैर कश्मीरी छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया।

5 अप्रैल – ग़ैर कश्मीरी छात्रों के एक दल ने एनआईटी डायरेक्टर से मुलाकात कर अपनी मांग रखी। इनमें अपनी सुरक्षा के साथ लाठीचार्ज के लिए ज़िम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की बात की। मांगपत्र सौंपने के बाद ग़ैर कश्मीरी छात्रों ने मार्च निकालने की कोशिश की पर उन्हें रोक दिया गया। पुलिस ने एक बार फिर बर्बरतापूर्वक तिरंगा मार्च निकाल रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया, कई छात्रों को गंभीर चोटें आईं। कैंपस में सीआरपीएफ़ की तैनाती की गई।

6 अप्रैल – इस घटनाक्रम के चार दिन बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दो सदस्यीय टीम कश्मीर पहुँची, जिसने अधिकारियों और छात्रों से मुलाक़ात की। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में अपने बयान जारी कर छात्रों को सुरक्षा का आश्वासन दिया।

7 अप्रैल – जम्मू कश्मीर पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ़ विभिन्न राजनीतिक दलों ने जम्मू में बंद रखा। जम्मू– कश्मीर राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह ने एनआईटी मामले की जांच के लिए

एडिशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच किये जाने के आदेश दिये।

13 अप्रैल – एनआईटी श्रीनगर के स्थानांतरण की मांग को लेकर एनआईटी छात्रों ने दिल्ली के जंतर–मंतर पर धरना–प्रदर्शन किया। साथ ही मांग की कि घटना में गैरकश्मीरी छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लिया जाए।

19 अप्रैल – सरकार द्वारा मांग न माने जाने पर एनआईटी श्रीनगर के छात्रों ने एक बार फिर जंतर–मंतर पर डेरा डाला। इस बार उनका पूरा जोर परिसर स्थानांतरण और एनआईटी परिसर में तिरंगा फहराये जाने पर रहा। इसी दिन, छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल एनआईटी श्रीनगर के निदेशक डॉ. रजत गुप्ता और मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात कर अपनी बात रखी थी।

20 अप्रैल – एनआईटी प्रशासन को छात्रों की मांगों के आगे झुकना पड़ा। एनआईटी प्रशासन ने फैक्ट फाइंडिग कमेटी का पुर्नगठन, निश्चित अवधि निर्धारण, छात्र परिषद् की स्थापना, परीक्षा का बाह्य–मूल्यांकन एवं छात्रों की सुरक्षा के साथ परिसर में राष्ट्रीय त्यौहारों को मनाये जाने की स्वीकृति दी।

क्या कहना है छात्रों का ...

एनआइटी श्रीनगर के 75 फीसद छात्र बाहरी हैं, जिनमें से अधिकांश वापस घरों को लौट गए हैं। उन्हें 25 अप्रैल तक कैंपस में लौटने का नोटिस मिला है। विनायक का कहना है कि हमारी सुरक्षा की गारंटी सिर्फ बातों से नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर पूरी की जानी चाहिए।

विनायक शर्मा, श्रीनगर

हमने अपनी मांग को परिसर में आए एचआरडी अधिकारियों के समक्ष उठाया लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। ऐसे में हम चाहते हैं कि एनआईटी में गैर–कश्मीरी छात्रों के खिलाफ दर्ज किये गए सभी मामले वापस लिए जाएं और सभी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए।

सौरभ सिंह, श्रीनगर

छात्रों की सुरक्षा को लेकर सरकारें सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं। चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों ही सिर्फ कश्मीर को लेकर राजनीति करने में लगी हैं।

गौतम किशोर, श्रीनगर

हमारी कुछ मांगों को एनआईटी प्रशासन ने भले मान लिया है मगर हमें अब भी परिसर में जाने और क्लास करने में भय है कि कहीं हम पर हमला ना हो। क्योंकि जिन छात्रों ने हमें खुलेआम धमकी दी वो अब भी परिसर में आजाद हैं, उन पर ना तो कोई कार्रवाई की गयी। साथ ही वहां के शिक्षकों के लिए भी कोई निर्देश सरकार ने दिए। ऐसे में हमारी शारीरिक के साथ शैक्षिक सुरक्षा का मामला भी अधूरा है।

स्वयं गुप्ता, श्रीनगर

भले ही हम श्रीनगर स्थित एनआईटी परिसर में पढ़ते हों पर वहां के शिक्षक और स्थानीय छात्र हमें अपना नहीं मानते। वे हमें भारतीय होने के नाते हेय दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में जरूरी है कि परिसर में भारतीय तिरंगा लहराया जाये, मगर सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है।

रजत श्रीवास्तव, श्रीनगर

उमर-अनिर्बान प्रतिबंधित, कन्हैया कुमार पर दस हजार जुर्माना

जांच समिति की रिपोर्ट में 14 छात्र दोषी, सभी पर लगा आर्थिक दंड

नई दिल्ली। संसद हमले के दोषी अफजल गुरू की बरसी मनाने और देशविरोधी नारेबाजी करने की घटना में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर नौ फरवरी की घटना में दोषी पाए गए छात्र अनिर्बान भट्टाचार्य को पांच साल के लिए कैंपस में प्रतिबंधित कर दिया गया है।

दो पूर्व छात्राओं बनज्योत्सना और द्रौपदी घोष पर भी पांच साल का प्रतिबंध लगाया गया है। जबकि उमर खालिद को छह माह तथा पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष आशुतोष को एक साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। आशुतोष कुमार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए तत्काल प्रभाव से हॉस्टल की सुविधा भी उनसे ले ली गई है। इस क्रम में जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर भी दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुल 14 छात्रों को आथिक दंड दिया गया। इनमें 12 छात्रों पर 20—20 हजार और दो छात्र पर 10—10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।

विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'गवाही, वीडियो क्लिप्स देखने (जेएनयू सुरक्षा द्वारा प्रदान किया गया और फॉरेंसिक टेस्ट द्वारा सत्यापित), रिकार्ड पर दस्तावेजों की जांच के बाद उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय ने तीनों छात्रों को निष्कासित करने फैसला किया।'

वहीं, विवादित कार्यक्रम के मुख्य आयोजकों में एक अनिर्बान भट्टाचार्य को पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरान उसे जेएनयू के किसी कोर्स में दाखिला भी नहीं दिया जाएगा। यदि कोई इस बीच हॉस्टल या अपने आवास पर उसे बुलाता है तो उसके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा मुजीब गट्टू को भी एक वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। जबकि एक अन्य छात्रा ऐश्वर्या अधिकारी पर भी जुर्माना लगाया गया है जबकि उनका नाम रिपोर्ट में नहीं था।

विवादित कार्यक्रम की जांच के लिए विश्वविद्यालय द्वारा बनायी गयी एक उच्च स्तरीय कमेटी ने कार्यक्रम को लेकर आपत्ति जताने वाले जेएनयू छात्रसंघ के संयुक्त सचिव सौरभ कुमार को आयोजन के दिन यातायात रोकने का 'दोषी' पाया और उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। छात्रों को 13 मई तक जुर्माने की राशि भरनी होगी। ऐसा न करने पर उनको हॉस्टल से बाहर कर दिया जाएगा और अगले सेमेस्टर में दाखिला भी नहीं दिया जाएगा।

बतादें कि इसी वर्ष बीते नौ फरवरी को विश्वविद्यालय प्रशासन से कविता पाठ 'ए कंट्री विदाउट ए पोस्ट' के लिए कुछ छात्रों ने अनुमति ली थी। लेकिन जैसे ही जेएनयू प्रशासन को पता चला कि ये छात्र कविता पाठ न करके अफजल गुरू का शहीदी दिवस मनाएंगे, इनकी अनुमति रद कर दी। इसके बाद कार्यक्रम आयोजित करने वाले छात्रों ने साबरमती ढाबा और गंगा ढाबा पर सभा की और कुछ छात्रों ने देश विरोधी नारे भी लगाए थे। मीडिया में मामला आने के बाद जेएनयू प्रशासन ने शुरू में आठ छात्रों को हॉस्टल व शैक्षणिक गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया था। और पहले तीन सदस्यीय फिर पांच सदस्यीय समिति बनाकर इसकी जांच के आदेश दिए जिसने 11 मार्च को रिपोर्ट सौंपी। आंतरिक समिति की रिपोर्ट में 21 छात्रों को दोषी बताया था। फिलहाल ये सभी छात्र छह महीने की जमानत पर बाहर हैं। इन छात्रों पर राजद्रोह का केस चल रहा है। ■

देशभक्ति अपराध है तो बार-बार करूंगा : सौरभ शर्मा

प्रशासनिक फैसले के खिलाफ छात्र संघ, दबाव में कार्रवाई का लगाया आरोप

नई दिल्ली। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर 14 छात्रों पर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन द्वारा की गयी कार्रवाई के निर्णय को जेएनयू छात्र संघ ने नकार दिया है। छात्र संघ के कुछ पदाधिकारी इसे बदले की राजनीति बता रहे हैं तो कुछ इस निर्णय को सिर्फ समझौता करार दे रहे हैं।

जेएनयू छात्र संघ की उपाध्यक्ष शेहला रशीद ने प्रशासन के फैसले को नकारते हुए उसे बदले की भावना से प्रेरित फैसला करार दिया है। उनका कहना है कि जेएनयू के कुलपति केंद्र सरकार से सीधे निर्देश ले रहे हैं और इसी का नतीजा है कि छात्रों के प्रति इस प्रकार के कठोर फैसले लिए गये हैं। ऐसे में यह निर्णय हमारे लिए अमान्य है।

वहीं, छात्र संघ सचिव रामा नागा का कहना है कि यह निर्णय पक्षपातपूर्ण होकर लिया गया है। इस निर्णय से कई छात्रों का भविष्य खराब हो सकता है। हम इस निर्णय के खिलाफ अदालत में अपील करेंगे।

जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता और जेएनयू छात्रसंघ के संयुक्त सचिव सौरभ कुमार शर्मा ने कहा कि जेएनयू प्रशासन ने जो निर्णय लिया है वह जेएनयू शिक्षक संघ के दबाव में लिया है। यह न्याय नहीं समझौता है।

खुद पर लगे जुर्माने के बारे सौरभ शर्मा ने कहा कि उनपर बस में सवार होकर देश विरोधी नारे लगाते बाहर जा रहे लोगों को रोकने का आरोप है। जुर्माने के साथ यह भी कहा गया है भविष्य में वो किसी भी देश विरोधी गतिविधियों में हस्तक्षेप न करूं। सौरभ ने कहा, 'अगर भारत माता के अपमान के विरोध में खड़ा होना अपराध है और उसकी यह सजा है.. तो मैं अपनी अंतिम सांस तक यह अपराध बार–बार करता रहूंगा।'

विद्यार्थी परिषद् ने राष्ट्रपति से लगाई रक्षा की गुहार

जेएनयू में 9 फरवरी को हुए विवादास्पद कार्यक्रम के मामले में खुद को दंड दिए जाने का विरोध करते हुए अभाविप सदस्य सौरभ शर्मा ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से राष्ट्रवादियों और जिम्मेदार छात्रों की रक्षा करने की अपील की।

सौरभ ने राष्ट्रपति को एक पत्र में कहा है, "मैंने जेएनयू के अन्य जिम्मेदार नागरिकों और राष्ट्रवादी छात्रों के साथ नौ फरवरी को देशद्रोही गतिवधियों का विरोध करते हुए जेएनयू प्रशासन को एक आपत्ति पत्र दिया था। उसी के अनुसार प्रशासन ने अनुमति वापस ले ली। हालांकि कुछ छात्र नेताओं के साथ आयोजकों ने कार्यक्रम किया।"

अभाविप छात्र नेता ने कहा कि जमावड़े का विरोध करने और भारत विरोधी कार्यक्रम का आयोजन करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी में कानून का साथ देने की उन्हें सजा दी गयी। जेएनयू प्रशासन भारत विरोधी छात्रों और राष्ट्रवादी छात्रों के बीच भेद करने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा, "मुख्य प्रॉक्टर के ऑफिस आदेश में भविष्य में ऐसे किसी कार्यक्रम–जुलूस का विरोध नही करने के प्रति मुझे आगाह भी किया गया है।"

सिर्फ अनिश्चितता ही निश्चित है...

✍ प्रस्वर जैन

निश्चित है तो सिर्फ घोर अनिश्चितता। अगला भोजन मिलेगा क्या? गला गीला करने के लिए कितनी दूर से पानी लाना पड़ेगा? बेजान हो चुके जानवरों को क्या सूखी घास भी नसीब होगी? परिवार जो आज साथ में है वो कल भी रहेगा?

यह भाव मराठवाड़ा की उस महिला के हैं जिसके पति ने फसल बर्बाद होने पर आत्महत्या कर ली थी। उसे यह नहीं पता था कि वह उस पर कितना कर्ज छोड़ गया है। उसे यह भी नहीं पता था कि उसके घर के, खेत के और, सबसे जरूरी, राशन के कागज़ किसके पास रखे हैं। उसने और उसके जवान बेटे–बहू ने कभी शहर नहीं देखा था। मजदूरी कर जीवन यापन करने का ख्याल उसके जेहन में ही नहीं था। मन में थी तो सिर्फ एक टीस कि पति ने उसे कभी कुछ बताया क्यों नहीं।

असहाय हो गयी थी वह, उन हजारों किसानो की तरह जो पानी की हर एक बूँद को ले कर संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष छोटा नहीं था। पीने का पानी उपलब्ध नहीं होने के बावजूद उद्योगों को पानी दिया जा रहा था। बड़ा किसान टैंकर खरीद कर अपने अनार और मौसंबी के बगीचों को बचा रहा था। शहर में लोग बोतलबंद पानी खरीद कर अपना काम चला रहे थे। परन्तु गांव में लोग जानवरों के साथ पानी की हर एक बूँद बांटने के लिए मजबूर थे। जब बांटने को कुछ बचा नहीं तो मजबूरी में जानवरों को दलालो के हाथ बेचना पड़ा।

बाज़ार में वह दृश्य देखने लायक था जब एक निरीह किसान अपने 70,000 रूपए के बैल को 40,000 में बेचने के लिए एक कसाई से मोल–भाव करता मिला। अंत में जैसे ही सौदा पक्का हुआ तब किसान ने चाबुक उठा बैल पर इतनी जोर से दे मारा की बैल तिलमिला कर दोनों पैर उठा हवा में उछल गया। यह संकेत था कि किसान ने बैल से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए है। अब उसका उस पर कोई अधिकार नहीं है। किसान और बैल की आँखें सुर्ख लाल थी, पर दोनों ने आंसू बहाने से मना कर दिया था। सर झुकाए वह किसान पैसे ले अपने घर चल पड़ा। सोच यह रहा था कि कुछ माह बाद यदि बारिश नहीं हुई तो उस बैल के दूसरे जोड़े को भी बाजार में ले के आना पड़ेगा।

उस किसान को यह चिंता भी सता रही थी कि जब कभी भी बारिश होगी तब उसके पास बैल खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। उसे फिर 700 रूपए प्रति घंटे की दर से ट्रेक्टर को खेत जोतने के लिए भी किराये पर लेना पड़ेगा। पर किराये पर लेने के लिए भी क्या तब तक कुछ बचेगा। बर्तन, जेवर, जमीन...घर? इस लिए बेहतर था शहर चले जाना।

मुंबई के उपनगरीय क्षेत्रो में बनते बहुमंजिला इलाकों में कभी शहर नहीं देखा हुआ ग्रामीण टिन से बनी झोपडियों में रहते हुए दिन–रात मेहनत कर रहा था। उसकी कोशिश गांव में रह रहे अपने बूढ़े माँ–बाप और निर्बोध बच्चों को जिंदा रखने की थी। साथ ही यह उम्मीद भी थी कि जब कभी भी बारिश हो वह फिर से अपने खेतों को उपजाऊ बना सके। बंधुआ मजदूर के जैसी नौकरी छोड कर अपना जीवन खुद अपने हाथो से गढ़ सके। इसी उम्मीद के साथ वह दिन–रात लगा हुआ था कि गांव उन्हें फिर से बुलाएगा।

गांव ने तो पहले से उस किसान को यह बता दिया था कि संभल जाओ नहीं तो तुम्हारी हमारी नहीं बनेगी। 1972 के दुष्काल के समय लोगों को चीख–चीख कर उसने कहा था कि मेरा शोषण करना बंद करो नहीं तो स्थिति विकराल होती जायेगी। बात समझाने के लिए कुछ लोगो को घास की रोटियां भी खिलाई। फिर भी नहीं समझे तो हर कुछ सालों बाद 1978, 1992,1997 और 2001 में गांव ने यही बात दोहराई। गन्ने के लालच और राजनीतिक लोभ ने किसी को कुछ समझने नहीं दिया। अभी भी गांव को शहर की मरहम–पट्टी की जा रही है।

बीमारी का इलाज तो सभी को पता है। शक्कर की खेती की जगह ज्वार–बाजरा जैसे कम पानी वाली फसल कम से कम पेट तो भर सकती हैं। बड़ी–बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की जगह छोटे–छोटे तालाब–बावड़ी इंसानों के साथ–साथ जमीन की भी प्यास बुझा सकते हैं। न नरेगा की जरुरत पड़ेगी, न ही पानी से भरे ट्रेन की। ना ही बड़े–बड़े विशेषज्ञों की, ना ही राजनेताओ की। एक आम किसान, जिसके नाम पर करोडों रूपए का भ्रष्टचार होता है, वह आत्महत्या करने के बजाय अपनी समस्याए खुद हल कर पायेगा। मानव केंद्रित साझा जीवन फिर यह मानव निर्मित प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सक्षम होगा। ■

उजागर हुआ वामपंथ का छद्म चेहरा

हैदराबाद। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। इस खुलासे के बाद कांग्रेस और वामपंथी छात्र संगठनों का छद्म चेहरा उजागर हो गया है। दोनों संगठनों ने अपने फायदे के लिए रोहित मामले पर जमकर राजनीतिक रोटी सेंकी है। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि बल्कि हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचसीयू) में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के एक वरिष्ठ छात्र नेता ने किया है। इतना ही नहीं इस छात्रनेता ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है।

विश्वविद्यालय की वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई से इस्तीफा देने वाले छात्र राज कुमार साहू की माने तो रोहित की मौत के बाद जिस तरह राजनीति शुरू हुई उससे वे बहुत निराश हैं। रोहित की मौत के चार महीने बाद भी इस मामले की सच्चाई सामने नहीं आ पायी सिर्फ राजनीति की गयी। साहू के मुताबिक, कांग्रेस और लेफ्ट सहित दूसरी अवसरवादी पार्टियां रोहित वेमुला के केस को अपने राजनीतिक फायदे के लिए भुना रही हैं। साहू ने कहा कि वाम दलों द्वारा रोहित वेमुला मामले में जिस प्रकार का गैर-जिम्मेदाराना कार्य किया गया और पूरे आंदोलन को मौकापरस्त बनाया गया, उसी से खिन्न होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है।

अपने इस्तीफे में राज कुमार साहू ने लिखा, "एसएफआई तथा एचसीयू में मौजूदा माहौल गंदा हो चुका है। एसएफआई की राजनीति अवसरवादी हो गई है और सिद्धांतों पर आधारित नहीं है।" उन्होंने कहा, 'मैं बाकी छात्रों से भी अपील करूंगा कि वे आंदोलन से हट जाएं और रोहित वेमुला मामले को संवैधानिक तौर पर अपनाएं। साथ ही, जेएससी, एसएफआई और एएसए छात्रों के बीच नफरत की राजनीति फैलाने के बजाए छात्रों की शैक्षिक प्रगति की दिशा में मिलकर कार्य करें। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए बनी जेएसी को रोहित वेमुला की मृत्यु के दिन से आज तक के सभी खातों (आर्थिक लेखा-जोखा) को सार्वजनिक करने के साथ आर्थिक स्रोत की जानकारी का भी खुलासा करना चाहिए।

➢रोहित बेमुला मामले में हुआ बड़ा खुलासा
➢कांग्रेस और वामपंथी दलों ने रची थी साजिश
➢रोहित को राजनीति फायदे के लिए मोहरा बनाया गया

इस पूरे प्रकरण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं को जिस तरह जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही थी, अब इस खुलासे के बाद धीरे-धीरे सारा सच सामने आने लगा है। अभाविप पहले ही इस प्रकार की किसी राजनीतिक साजिश की आशंका जता रही थी लेकिन उसकी बातों को दबाने की कोशिश की जा रही थी।

केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एम. वेंकैया नायडू ने माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट पर लिखा, "एचसीयू छात्र संगठन सचिव ने इस्तीफा दे दिया है और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं... रोहित वेमुला से जुड़े मामले में कांग्रेस और वामपंथियों की भूमिका की पोल खुल गई है..." ■

सिद्धांतनिष्ठ बलराज मधोक

✍ संजीव सिन्हा

भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष श्री बलराज मधोक नहीं रहे। 2 मई 2016 को 96 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। वे राष्ट्रवादी राजनीतिक आंदोलन के आधारस्तंभ थे, इसके साथ ही वे विचारक, इतिहासवेत्ता एवं लेखक भी थे। वे सिद्धांतनिष्ठ थे। राष्ट्रवादी विचारों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। वे बेबाक अपने विचार व्यक्त किया करते थे। संसद में वे राष्ट्रीय विचारों के प्रथम प्रवक्ता रहे। साठ के दशक में अपनी सक्रियता से उन्होंने अपार ख्याति अर्जित की। तब उन्होंने अपनी पुस्तक 'Indianisation' (भारतीयकरण) के माध्यम से बौद्धिक जगत में महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। उनके ही अध्यक्षीय काल में भारतीय जनसंघ चरमोत्कर्ष पर पहुंची और पार्टी ने 1967 के लोकसभा चुनाव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

श्री बलराज मधोक का जन्म कश्मीर में 25 फरवरी 1920 में हुआ था। उनका बचपन गुजरांवाला (अब पाकिस्तान) में गुजरा। उन्होंने जम्मू, श्रीनगर और लाहौर में पढ़ाई की। उनकी उच्च शिक्षा लाहौर विश्वविद्यालय में हुई। 18 वर्ष की आयु में अपने छात्र जीवन में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्पर्क में आये। सन 1942 में भारतीय सेना में सेवा (कमीशन) का प्रस्ताव ठुकराते हुए उन्होंने रा. स्व. संघ के प्रचारक के रूप में देश की सेवा करने का व्रत लिया। उन्हें कश्मीर में संघ की शाखाँ प्रारंभ करने के लिए कश्मीर भेजा गया। उन्होंने 'जम्मू कश्मीर प्रजा परिषद' के गठन में सहयोग किया।

श्री बलराज मधोक 1951 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने। वे संसद (लोकसभा) के दो बार सदस्य भी निर्वाचित हुए। 1966–67 में वह भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने। 1967 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ ने उनके नेतृत्व में 35 सीटें जीती जो उस समय तक का पार्टी का सबसे बेहतरीन चुनावी प्रदर्शन था। पंजाब व उत्तर प्रदेश में जनसंघ की संयुक्त सरकारें बनी और देश के 8 प्रमुख राज्यों में जनसंघ मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरा था। वैचारिक मतभेद के चलते 1973 में बलराज मधोक को भारतीय जनसंघ से मुक्त कर दिया गया, लेकिन वे अन्य किसी राजनीतिक दल में नहीं गए।

देश पर जब आपातकाल थोपा गया तो उन्होंने इसके विरुद्ध जमकर संघर्ष किया। इस दौरान उन्हें जेल में डाल दिया गया। जब आपातकाल हटा, तब वह जनता पार्टी में शामिल हुए और जनसंघ का इसमें विलय हो गया। 1979 में जनता पार्टी से इस्तीफा देकर उन्होंने जनसंघ को अखिल भारतीय जनसंघ का नया नाम देकर पुनर्जीवित करने का प्रयास किया।

राजनीति से अलग होकर भी वे निष्क्रिय नहीं रहे। अपनी लेखनी को कभी विराम नहीं दिया। बलराज जी उन नेताओं में से थे जो लगभग पैदाइशी लड़ाकू होते हैं और मृत्यु की शैया तक लड़ाकू ही रहते हैं। उन्होंने जिन्दगी को जीवन्तता से जीने का आदर्श सबके सामने रखा।

श्री बलराज मधोक द्वारा लिखी गई 30 से अधिक पुस्तकें, जिनमें उनकी आत्मकथा और उनका उपन्यास 'जीत या हार' अपने दौर के आईने है जिनमें वे सारे षड़यंत्र, सारी अदूरदर्शिता साकार हो उठती है। बलराज जी की प्रमुख पुस्तकें हैं:– विभाजित भारत में मुस्लिम समस्या का पुनरोदय, कश्मीर : जीत में हार, खण्डित कश्मीर, जीत या हार, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी – एक जीवनी, कश्मीर : सेंटर ऑफ न्यू अलाइन्मेंट्स, पाकिस्तान : आदि और अन्त, Hindustan on the Cross Roads, Portrait of a Martyr (Biography of Shyama Prasad Mukerjee), Kashmir: The Storm Center of The World, Bungling in Kashmir, Kargil and Indo&Pak Relations, Rationale of Hindu State, etc.

अभाविप का महाअभियान, समाज जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर होगा सर्वेक्षण

देश के वास्तविक हालात से अवगत कराएगी सर्वेक्षण रिपोर्ट

नई दिल्ली। भारत की आज़ादी को 68 साल बीत गए लेकिन देश आज भी कई समस्याओं से जूझ रहा है. ऐसा देखने को मिलता है कि ये समस्याएं वस्तुस्थिति की सही समझ नही होने व कागज़ी सर्वेक्षणों पर आधारित होते है, जो समस्याओं की असल तस्वीर प्रस्तुत नही करती. वही दूसरी ओर जिन निजी व विदेशी सर्वेक्षणों पर सरकार भरोसा करती है, उनके अपने उद्देश्य होते है. परिणामतः बड़ी–बड़ी योजनाएं भी विफल हो जाती हैं, ज़मीनी स्थिति में कोई सुधार नही होता और समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने अपने सामाजिक दायित्वों को समझते हुए समाज जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर पूरे देश में सामाजिक सर्वेक्षण–2016 कराने का निर्णय लिया है।

इस सर्वेक्षण के तहत परिषद् कार्यकर्त्ता देशभर में घर घर जायेंगे और आतंकवाद, नक्सलवाद, घुसपैठ समस्या, किसान आत्महत्या, धर्मान्तरण, महिला उत्पीड़न जैसे विषयों से जुड़े विविध पहलुओं की जानकारी जुटाएंगे। उद्देश्य होगा – देश की वास्तविक हालात, समस्या व समाधान के उपायों से संबंधित जानकारी इकठ्ठा करना और उस जानकारी के आधार पर सरकार, समाज को जागरूक करना ताकि जरुरी कदम उठाये जा सकें।

12 मई से 20 मई तक चलनेवाले इस आठ दिवसीय अखिल भारतीय सर्वेक्षण अभियान में परिषद् कार्यकर्त्ता आमजन के अलावा सामाजिक–जातिगत संगठनों, राजनीतिक दलों, प्रशासनिक पदाधिकारियों, व्यापारियों, शासकीय–गैर शासकीय कर्मचारियों के साथ साथ समाज–जीवन के विभिन्न वर्गों से संपर्क करेंगे और उनसे संवाद कर जानकारी जुटाएंगे। इस कार्य में प्रत्येक जिले के कम से कम 50 कार्यकर्त्ता लगेंगे। प्रवासी कार्यकर्ताओं के अलावा सर्वेक्षण की इस मुहिम से विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों को भी जोड़ने की योजना है। कार्यकर्ता महाविद्यालय में बैठक, कक्षा में संपर्क, पत्रक वितरण आदि के माध्यम से युवा विद्यार्थियों को भी जोड़ेंगे।

इस अनूठे अभियान के तहत 34 विषय चुने गए है, जिनमें आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अनुसूचित जाति–जनजाति से जुड़ी समस्याओं से लेकर शिक्षा का व्यापारीकरण, सुखाड़–बाढ़ की समस्या, किसान आत्महत्या जैसे संवेदनशील मुद्दे हैं तो वहीं स्वच्छता, नशा–खोरी, जाति व्यवस्था, कुपोषण, दहेज़ प्रथा, पलायन जैसे सामाजिक मुद्दे भी विशेष रूप से शामिल किए गए है. इस सामूहिक सर्वेक्षण में कुछ राज्यों के लिए विशेष विषय तय किए गए हैं, जिन्हें कार्यकर्त्ता सर्वेक्षण के दौरान जानकारी इकठ्ठा करते वक़्त विशेष ध्यान रखेंगे. इनमें आतंकवाद से जुड़ी समस्या पर केरल, कर्नाटक, जम्मू–कश्मीर, पंजाब व पूर्वोत्तर राज्य से जानकारी इकठ्ठा की जायेगी, वहीं नक्सलवाद से जुड़ी जानकारी नक्सल प्रभावित राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं महाराष्ट्र से जुटाई जायेगी. इसी तरह घुसपैठ से संबंधित जानकारी असम सहित अन्य पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल एवं बिहार से, किसान आत्महत्या पर महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश व पंजाब से, कन्याभ्रूण हत्या पर पंजाब व हरियाणा से, धर्मान्तरण पर पूर्वोत्तर राज्य, झारखण्ड, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश व तेलंगाना से, महिला उत्पीड़न पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं झारखंड से व ईसाई मिशनरी की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी केरल, पूर्वोत्तर राज्य, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व देश के अन्य जनजातीय बहुल इलाकों से जुटाई जायेगी।

इस सर्वेक्षण के दौरान विद्यार्थियों का दल जन–प्रतिनिधियों और प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा

गांव में उपलब्ध कराए गए संसाधनों का ब्योरा भी इकट्ठा करेंगे। इसके साथ ही पूर्व में चलायी गयी योजनाओं के परिणाम व आनेवाले दिनों की योजनाओं के बारे में सूचनाएं एकत्रित करेंगे। सर्वेक्षण के बाद सभी जानकारियों की विषयवार छंटनी कर सूचनाएं एकत्रित की जायेंगी, जो अंततः एक विस्तृत रिपोर्ट में तब्दील की जायेगी। यह रिपोर्ट न केवल देश की वस्तुस्थिति से लोगों को अवगत कराएगा बल्कि इसे राज्य व भारत सरकार को भी सौंपा जाएगा ताकि सरकार वास्तविक स्थिति से अवगत हो सके तथा महत्वपूर्ण निर्णय ले सके, जो इन समस्याओं से देश को निजात दिलाने में मदद करें।

विदित हो कि विद्यार्थी परिषद् पूर्व में भी ऐसे सर्वेक्षण कराती रही है, जिसने सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने को मजबूर किया। इनमें अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थियों के छात्रावास, पंजाब में नशा की समस्या व बांग्लादेश से सटे इलाकों में किए सर्वेक्षण प्रमुख है। **(अभिषेक रंजन की रिपोर्ट)**

बाबा साहेब अंबेडकर रखा जाए जेएनयू पुस्तकालय का नाम

नई दिल्ली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (अभाविप) ने मांग की है कि जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय का नाम बदलकर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय रखा जाए और वहां भारतीय संविधान निर्माता की एक प्रतिमा भी स्थापित की जाए। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय कार्यकारी परिषद ही इस तरह के किसी प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है।

जेएनयू छात्र संघ के संयुक्त सचिव सौरभ शर्मा ने कहा, "हम मांग करते हैं कि जेएनयू केंद्रीय पुस्तकालय का नाम बदलकर अम्बेडकर पुस्तकालय किया जाए तथा परिसर में दलित अधिकारों के मसीहा की प्रतिमा होनी चाहिए। इसके अलावा हम मूल संविधान की प्रति भी चाहते हैं ताकि छात्रों को संविधान के पाठन का भी मौका मिले।" उन्होंने कहा कि परिषद् रजिस्ट्रार एवं कुलपति से मांगों पर गौर करने की अपील करने के साथ विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की अगली बैठक में भी एक प्रस्ताव रखेगा।

अभाविप कार्यकर्ताओं ने ली 'जल संरक्षण की शपथ'

पीलीभीत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जल संरक्षण को लेकर नई मुहिम छेड़ी है। इसके तहत अभाविप कार्यकर्ताओं ने लोगों को जागरूक करने के साथ स्वयं भी जल संरक्षण करने की शपथ ग्रहण की। शहर से लेकर गांव तक जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किए जाने को लेकर योजना तैयार की गयी है, जिससे पानी की बचत की जा सकेगी।

उपाधि महाविद्यालय में एकत्रित अभाविप कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वह जल का प्रयोग कम से कम करेंगे, ताकि आने वाले समय में जल की कमी नहीं होगी। जल संरक्षण की मुहिम के तहत लोगों को पानी की कमी से होने वाली परेशानियों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

अभाविप के जिला संयोजक जीतू सूर्या ने कहा कि तेज गर्मी की वजह से पानी की किल्लत हो रही है। इसके बावजूद पानी का कम से कम इस्तेमाल करने की आदत डालनी होगी, तभी जल संरक्षण किया जा सकेगा। पानी का दुरुपयोग बंद कर दूसरे व्यक्ति की प्यास बुझाई जा सकती है। पानी के बगैर जीवन असंभव है। हमें पानी की बचत करनी चाहिए।

शिक्षा

गरीब एवं मेधावी छात्रों के हित में फैसला

✍ श्रीरंग कुलकर्णी

हमने अपनी शिक्षा प्रणाली को व्यापार बना दिया है और इस खेल में सरकार, कॉर्पोरेट, समाज, नेता और पेरेंट्स सभी शामिल हैं। अच्छी शिक्षा तक पहुंच पैसे वालों तक ही सीमित हो गई है, यह लगातार आम आदमी के पहुंच से बाहर होती जा रही है। ऐसे में हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला गरीब और मेधावी छात्रों एवं उनके अभिभावकों को जरूर राहत पहुंचाएगा। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद मध्य प्रदेश सरकार को यह अधिकार होगा कि वह सरकारी एवं निजी दोनों ही संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना के संदर्भ में नियम तय करे। जाहिर है, इस फैसले पर राज्य सरकार सख्ती से अमल करती है, तो न केवल शिक्षा के व्यापारीकरण पर लगाम लगेगी, बल्कि शिक्षा संस्थानों की मनमानी पर भी नकेल कसी जा सकेगी। शिक्षा संस्थापनों द्वारा छात्रों के शोषण और उनसे मनमानी फीस वसूलने के खिलाफ वर्ष 2006 में जबलपुर उच्च न्यायालय में निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों के बारे में अभाविप द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने तब मध्य प्रदेश सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के पी. ए. इनामदार फैसले का हवाला देते हुए जल्द कानून बनाने के निर्देश दिए थे।

उच्च न्यायालय के निर्देश के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने 2007 में 'प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एक्ट–2007' का गठन किया। 23 अप्रैल, 2007 को निजी दंत चिकित्सा संस्थान संगठन (एपीडीएमसी) ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके कहा कि इस नए एक्ट में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। सुनवाई चलती रही और 2009 में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि सरकारी और निजी कॉलेजों के लिए सरकार ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा ले और उसी से निजी कॉलेजों में भी प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाए। इस फैसले के बाद 2009 में निजी संस्थानों ने फिर सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई। वर्ष 2009 के बाद से लंबित पड़े इस मामले में फरवरी 2016 को सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आखिरी फैसला हाल ही में सुनाया है। इस फैसले के मुताबिक प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना को तय करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा और इसमें निजी महाविद्यालयों के किसी भी अधिकार का हनन नहीं होता।

उल्लेखनीय है कि गरीब एवं मेधावी विद्यार्थियों के हित में छात्र संगठन इस मामले को जोर–शोर से उठाते रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस मामले पर लंबे समय से आवाज उठाती रही है और न्यायालय में इस संदर्भ में याचिका भी दायर की हैं। अब माना जा रहा है कि यह फैसला गरीब एवं मेधावी छात्रों को पारदर्शी एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था देने एवं उनके भविष्य को संजोने में मददगार होगा। बेहतर होगा कि केंद्र सरकार भी इस संबंध में कानून बनाए और अन्य राज्यों की सरकारों को भी इस फैसले से जरूर सबक लेना चाहिए।

देशभर में सिर्फ उच्च शिक्षा ही नहीं तो केजी (KG) से पीजी (PG) तक सभी स्तर पर शिक्षा का व्यापारीकरण चल रहा है। स्कूली शिक्षा में भी हालात कुछ इसी तरह के हैं। अभिभावकों के लिए अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाना और उसी के साथ घर का भरण–पोषण करना मुश्किल हो रहा है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार सीबीएसई स्कूलों में आर्थिक तौर पर पिछड़े गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। जबकि शिक्षा माफिया दोनों हाथों से अच्छी शिक्षा के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। स्कूलों के इंचार्ज रि–एडमिशन, डेवलपमेंट फंड, एनुअल फीस चार्ज, महंगी यूनिफॉर्म और किताबों के नाम पर

हर साल लाखों रुपया बच्चों के अभिभावकों से ऐंठ रहे है। एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से सरकारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट और बदनाम किया गया है और आज स्थिति यह बन गई है कि सरकारी स्कूल मजबूरी का ठिकाना बन कर उभरे हैं, जो परिवार थोड़े से भी समर्थ होते हैं, वे अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के प्राइवेट स्कूलों की शरण में भेजने में देरी नहीं करते हैं। हालांकि इन प्राइवेट स्कूलों की हालत भी बदतर है। हमारी शिक्षा में यह एक ऐसा वर्ग विभाजन है, जिसकी लकीरें पूरी तरह से स्पष्ट हैं। भारत में महाराष्ट्र, कनार्टक, तमिलनाडु, राजस्थान व झारखंड जैसे राज्यों में परीक्षा कंट्रोल एक्ट लागू हैं। पंजाब में भी इसी तर्ज पर कानून बनाए जाने की मांग उठ रही है। शिक्षा व्यवस्थाथ को पारदर्शी एवं सर्वस्पर्शी बनाए जाने को लेकर इस तरह के विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। एक ऐसे समय में, जब सरकारें शिक्षा को चैरिटी का विषय न मानते हुए, उसे व्यापार का दर्जा देने में जुटी हैं, ऐसी पहल महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

(लेखक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मीडिया तथा जनसंपर्क प्रमुख हैं।)

अभाविप की 'राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद्' बैठक जम्मू में

जम्मू। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (अभाविप) के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की बैठक 28 से 31 मई, 2016 को जम्मू (जम्मू–कश्मीर) में आयोजित होगी। इस तीन दिवसीय बैठक में पहले दिन शाम को राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् के सम्मानार्थ नागरिक अभिनन्दन समारोह का आयोजन भी किया जायेगा।

बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के साथ शैक्षिक, सामाजिक, राष्ट्रीय मुद्दों तथा जम्मू–कश्मीर से संबंधित विषयों पर प्रस्ताव भी पारित किए जायेंगे। तत्पश्चात् बैठकों के दौर में विभिन्न विषयों जेएनयू जैसे संभावित घटनाएं एवं आगामी दिशा, वर्तमान परिस्थिति एवं आगामी योजनाएं, नई शिक्षा नीति पर चर्चा–सुझाव और केंद्र सरकार की शैक्षिक नीतियों पर समीक्षा आदि विषयों पर गहन चर्चा की जायेगी।

इसके अलावा, परिषद के संगठनात्मक विस्तार–विकास पर चर्चा के साथ समीक्षा एवं आगामी आग्रह के मुद्दों पर विचार व्यक्त किए जायेंगे। सदस्यता की विशेष योजना, गुणात्मक विशेष मुद्दों पर प्रांतों की योजना एवं उपलब्धि, प्रांत अभ्यास वर्ग–2016 जैसे विषयों पर विचार–विमर्श किया जाएगा। साथ ही, शैक्षिक मुद्दों पर परिसरों में संघर्ष, वैचारिक बहस–प्रबोधन एवं प्रशिक्षण की व्यापक योजना, विविध कार्य एवं आयाम की समीक्षा तथा सामाजिक दर्शन–अनुभूति (सर्वे) की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर आगामी दिशा तय किये जाने पर भी मंथन किया जाएगा।

बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् के सभी सदस्यों, सभी प्रांतों के अध्यक्ष व मंत्री के साथ मुंबई, हैदराबाद एवं बैंगलोर के महानगर अध्यक्ष–मंत्री व संगठन मंत्री सहित कुछ विशेष आमंत्रित कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस दौरान कार्यकर्ता विभिन्न कार्य/आयाम एवं राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् के गुट में कई विषयों पर मंथन करेंगे। जिसमें विकासार्थ विद्यार्थी (एसएफडी), थिंक इंडिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जनजाति कार्य, मेडिविजन (एलोपैथी), जिज्ञासा (आयुर्वेद छात्र), सांस्कृतिक समूह, छात्रा कार्य, कृषि छात्र, विश्व विद्यार्थी युवा संगठन (WOSY) एवं एनएसएस/एनसीसी जैसे आयाम के कार्यकर्ताओं की भी उपस्थिति रहेगी।

अभाविप ने नई शिक्षा नीति पर स्मृति ईरानी को दिए सुझाव

नई दिल्ली। नई शिक्षा नीति को लेकर अभाविप के 15 सदस्यीय दल ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात कर उन्हें अपने सुझाव सौंपे। दल का कहना था कि उनके सुझावों पर अमल करने से काफी संख्या में छात्रों को फायदा पहुंचेगा, जिससे छात्रों को अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफलता मिलेगी।

अभाविप कार्यकर्ताओं ने कहा कि उच्चशिक्षा में योग, आयुर्वेद, संगीत और पारंपरिक नृत्य, मनोविज्ञान, दर्शन, संस्कृत, बौद्ध धर्म इत्यादि में शोध के लिए विदेशी छात्रों को भी बढ़ावा देते हुए विदेश के कई सारे विश्वविद्यालय से विनिमय कार्यक्रम से भी जोड़ा जाये। नेक की रैंकिंग सभी विश्वविद्यालयों के लिए आवश्यक करना और साथ ही साथ नेक द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को प्रतिक्रिया भी दिया जाये।

सुझावों में कहा गया कि छात्राओं के लिए प्रोफेशनल कोर्स में स्नातक तक एवं नॉन प्रोफेशनल कोर्स में स्नातकोत्तर तक शुल्क माफ हो, साथ ही छात्राओं के लिए अधिक छात्रावासों की सुविधा उपलब्ध हो। अनुसूचित जाति–जनजातीय, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना और अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति देने के सुझाव भी दिए गये।

प्रतिनिधि मंडल में अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ नागेश ठाकुर, महासचिव विनय बिदरे, आयोजक सचिव सुनील अम्बेकर, प्रोफेसर एवं जेएनयू छात्रसंघ के सहसचिव सौरभ शर्मा सहित कई छात्रनेता शामिल रहे।

कॉलेजों द्वारा जुर्माना वसूली का अभाविप ने किया विरोध

अंबाला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की अंबाला इकाई ने कुछ कॉलेजों द्वारा विद्यार्थियों से जुर्माने की आड़ में किए जा रहे शोषण का विरोध किया है। साथ ही इस संबंध में उपायुक्त सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया।

अभाविप के जिला सह संयोजक माधव रावत ने कहा कि जिस प्रकार कॉलेजों में मनमाने ढंग से जुर्माना वसूला जा रहा है वह छात्रों के साथ अन्याय है। इस प्रकार की गतिविधि से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है। इसी विषय को लेकर परिषद् ने सभी कॉलेजों को ज्ञापन सौंपा है। माधव रावत ने बताया कि छात्रों की समस्याओं का जल्द निस्तारण करने तथा उनकी मदद के लिए निकट भविष्य में विद्यार्थी परिषद् की सभी कॉलेज में इकाई के गठन का काम भी जल्द पूरा हो जायेगा।

इसके अलावा, विभाग सह संयोजक करण सरना और नगर अध्यक्ष सौरव त्रिखा ने पिछले साल के काम की समीक्षा और आने वाले दिनों में आगामी योजना बनाए जाने को लेकर बैठक आहूत होने की भी घोषणा की जिसमें छात्रों से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण में अभाविप की जिम्मेदारी को लेकर चर्चा भी की जायेगी।

सामाजिक समरसता के प्रतीक थे बाबा साहब : जी. लक्ष्मण

संविधान के शिल्पी को अभाविप ने किया श्रद्धा-सुमन अर्पित

नई दिल्ली। संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीम राव अंबेडकर की 125वीं जयंती को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने देश भर में समरसता दिवस के रूप में मनाया। अंबेडकर जयंती के अवसर पर कहीं भव्य शोभा यात्रा निकाली गई तो कहीं छात्र सभा का आयोजन किया गया।

भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर की सोच काफी दूरदर्शी था। उनका मानना था कि कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर सकता है जब उस देश कि जनता में समरसता का भाव हो। जातिवाद और छुआछूत देश के विकास में बाधक है। बाबा साहब ने संविधान बनाते समय गरीब, पिछड़े अनुसूचित जाति/जनजाति का विशेष ख्याल रखा और उसे समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा का मंत्र दिया। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बाबा साहेब सामाजिक समरसता के प्रतीक थे।

उक्त बातें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जी. लक्ष्मण ने हैदराबाद में अभाविप द्वारा आयोजित डॉ. भीम राव अंबेडकर जयंती समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में अंबेडकर जी के विचार प्रासंगिक हैं।

वहीं देश की राजधानी **दिल्ली** में अंबेडकर जयंती के अवसर पर अभाविप द्वारा सम्मान समारोह(उनका सम्मान, जो रखते हैं ध्यान देश की स्वच्छता का) का आयोजन कर स्वच्छता अभियान में विशिष्ट योगदान देने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के कर्मचारियों को सम्मानित किया। अभाविप और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के संयुक्त तत्वाधान में दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में भव्य शोभायात्रा "एक यात्रा समरस भारत के लिए..." निकाल कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभाविप के प्रदेश संगठन मंत्री अजय ठाकुर ने कहा कि बाबा साहेब के विचारों को वर्तमान संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने जो समरसता का स्वप्न देखा था, उसे आज हम सबको पूरा करने की आवश्यकता है। साथ ही बाबा साहब के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने वालों से समाज को आगाह कराना बहुत जरूरी है।

इस मौके पर प्रदेश संगठन मंत्री भरत खटाना ने अभाविप की संगठनात्मक पृष्ठभूमि रखते हुए डॉ. अंबेडकर को दूरदर्शी सोच रखने वाला महापुरूष बताया और उनके विचारों पर पर अमल करने की बात कही।

जमशेदपुर में बाबा साहब के जयंती के अवसर पर मौजूद वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन परिचय और उनके उद्देश्य से कार्यकर्ताओं को परिचित कराते हुए कहा कि डॉ. अंबेडकर ने जो समरस भारत का सपना देखा था उन सपनों को पूरा करने का दायित्व हमसभी का है। जब तक किसी समाज में जाति–पाति का भेदभाव रहेगा तब तक वह राष्ट्र/समाज कभी उन्नत नहीं हो सकता। हम सभी भाई–भाई हैं कोई बड़ा या छोटा नहीं है। छुआछूत कैंसर से भी भयावह है, आइये हम सब मिलकर गरीब, दलित, पिछड़ा और वनवासी के हितों की रक्षा का संकल्प लें। इस दौरान अभाविप कार्यकर्ताओं ने डॉ. अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही डॉ. अंबेडकर द्वारा प्रदत्त आरक्षण व वनवासी–पिछड़ो के हितों की रक्षा का संकल्प लिया।

झालावर (राजस्थान) में अभाविप कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा का माल्यार्पण कर गगनभेदी नारों से जयघोष किया और विशाल शोभा यात्रा निकाली। इसमें डॉ. अंबेडकर, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, स्वामी विवेकानंद की झांकी के साथ सैंकड़ों विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला संयोजक विवेक दुबे ने शोभा यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि डॉ. अंबेडकर एक युगदृष्टा थे उनकी सामाजिक संकल्पना इसका जीता जागता उदाहरण है।

करनाल (हरियाणा) में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर जन्मदिवस पर अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया। मानव सेवा संघ में अभाविप द्वारा आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथी मेयर रेणु गुप्ता ने डॉ. भीमराव अंबेडकर को समरसता का प्रतीक बताया और युवाओं को उनके पदचिह्नों पर चलने की प्रेरणा दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी को संविधान का पालन करना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता व रा. स्व. संघ के विभाग प्रचारक नरेन्द्र जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और सामाजिक सुधारक के रूप में उनकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि बाबा साहब ने अपना दीपक खुद जलाया और समाज को समरसता रूपी नई रोशनी प्रदान की। किसी भी विचारधारा का अंधाधुध अनुसरण नहीं करना चाहिए। प्रदेश मंत्री कुलदीप पुनिया ने राष्ट्रनिर्माण में युवाओं की भूमिका को अहम बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रो. अजय अहलुवालिया ने राष्ट्रनिर्माण की प्रक्रिया में डॉ. अंबेडकर के योगदान पर प्रकाश डाला। और वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं को बाबा साहेब के मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया।

इसी क्रम में **भोपाल में** अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने भोपाल नाके पर डॉ. भीम राव अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक प्याऊ का शुभारंभ किया। परिषद के प्रांत संगठन मंत्री विजय अठवाल ने प्याऊ का उद्घाटन करते हुए कहा कि बाबा साहब शिक्षा को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे वे खुःद प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने वंचित लोगों को उनके अधिकार के लिए शिक्षा को सबसे कारगर उपाय बताया। वे हमेशा समाज में समानता लाने के लिए प्रयासरत रहे। राष्ट्रनिर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है। साथ ही अभाविप बाबा साहब के सपनों को पूरा करने में प्रयासरत है।

भुवनेश्वर में अभाविप ने डॉ. अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर वृक्षारोपण कर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर प्रदेश संगठन मंत्री गोविंद नायक ने कहा कि जब तक पर्यावरण शुद्ध है तब तक हम स्वस्थ हैं। पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। साथ ही उन्होंने डॉ. अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉ. अंबेडकर का जीवन अनुकरणीय है। उनके जीवन में लाखों बाधा आईं फिर भी वे कभी अपने लक्ष्य से नहीं भटके और राष्ट्रनिर्माण में लगे रहे। उन्होंने बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर को आधुनिक भारत का निर्माता करार दिया।

इसी अवसर पर **रायपुर में** अभाविप द्वारा आयोजित अंबेडकर जयंती समारोह में आए छात्र–छात्राओं को संबोधित करते हुए रायपुर स्थित कृषि वि.वि. के छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉ. ओ. पी. कश्यप ने कहा कि बाबा साहब का जीवन संघर्ष की जीती जागती मिसाल है। हम सभी को बाबा साहब के विचारों को अपने दैनिक जीवन में उतारना चाहिए। तभी समाज में सामाजिक समरसता कायम हो पायेगी। वहीं एक छात्रावास में समारोह को संबोधित करते हुए अभाविप के प्रदेश संगठन मंत्री मधुसूदन जोशी ने बाबा साहब का जीवन परिचय कराते हुए कहा कि बाबा साहेब सामाजिक बंधुत्व संरचना के सृजनकार थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन ही देश व समाज के वंचित वर्गों के अधिकार के लिए समर्पित कर दिया।

परिचर्चा

मूल्य आधारित हो नई शिक्षा नीति

1948 में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा–प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हुआ था। इसके बाद 1952 में लक्ष्मीस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया। प्रस्ताव में 'राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल' युवक–युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जो अब तक चल रही है। वर्ष 1992 में शिक्षा समिति में थोड़ा बहुत संशोधन किया गया। परंतु स्वतंत्रता के बाद देश को एक समसामयिक स्तरीय शिक्षा नीति प्राप्त नहीं हो सकी। आज देश को एक ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता है जो छात्र में ज्ञानार्जन के साथ सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, मानवीय मूल्यों का विकास कर सके। देश को एक ऐसे लोक कल्याणकारी शिक्षा नीति की आवश्यकता है जिससे शिक्षा में गुणात्मक व रचनात्मक वृद्धि हो सके। नयी शिक्षा नीति को लेकर राष्ट्रीय छात्रशक्ति के सहयोगी उत्कर्ष श्रीवास्तव ने विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं से बात की।

नई नीति बनाने वालों को सबसे पहले वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण कर यह अनुमान लगाने का प्रयास करना होगा कि आज स्कूल–कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ रही भविष्य की पीढ़ी को किस प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा तकनीकी संदर्भों में अपना कार्यकारी योगदान देना होगा। लोगों के सामने जो विश्व उभर रहा है उसमें हिंसा, अविश्वास, युद्ध, शोषण, धर्मांधता, रूढ़िवादिता इत्यादि को खत्म करने के लिए सम्यक समझ देने का उत्तरदायित्व भी नई शिक्षा नीति को लेना होगा।

–नितिनेंद्र प्रताप सिंह, देशबंधु कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के सभी क्षेत्रों में जो नीतियां बनाई जा रही है वे तात्कालिक और दूरगामी दोनों ही दृष्टि से सार्थक दिखाई पड़ रही हैं, जिसका उदाहरण विद्यार्थियों के साथ–साथ शिक्षकों की शिक्षा को लेकर प्रयास भी हैं। इसी कारण से टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम पर भी जोर दिया जा रहा है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है कि वर्तमान शिक्षा नीति जहां एक तरफ रोजगारपरक शिक्षा पर जोर दे रही है... वहीं दूसरी ओर संस्कृत भाषा और इतिहास के प्रति भी संवेदनशील है। विशेष बात ये भी है कि तकनीक का प्रयोग और निर्भरता पर समग्र जोर दिया जा रहा है। हालांकि शिक्षा का रोजगार में समायोजन सभी सरकारों के लिए चिंता का विषय रहा है।

–मृत्युंजय परमार राव, शोध छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

शिक्षा के विस्तार का लक्ष्य तो हमने एक हद तक प्राप्त कर लिया है। अब जरूरत है शिक्षा में गुणवत्ता लाने की तथा जीवन निर्माण से जोड़कर इसे जीवन्त बनाने की। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सरकार को नई शिक्षा नीति निर्माण करने की आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था में सबकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने तथा शिक्षा में एकरूपता लाने के लक्ष्य से सरकार को जमीनी स्तर पर काम करना होगा। उच्च शिक्षा का अन्तरराष्ट्रीयकरण करना, शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, ये सब नई शिक्षा नीति के प्रमुख लक्ष्य होने चाहिए। बदलते परिप्रेक्ष्य में पुरानी नीति में ऐसे सुधार की जरूरत थी जिससे शिक्षा

व्यवस्था में हमारा विश्वास बढ़े और हम पूर्ण रूप से विकास की ओर अग्रसर हों।

– पूजा श्रीवास्तव, एम.फिल., दयालबाग शैक्षणिक संस्थान, आगरा

समकालीन सरकार शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किए हुए है। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता, भ्रष्टाचार को रोकने हेतु नियुक्तियों में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि इस दिशा में अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं लेकिन उसका प्रतिफल दिखना शुरू नहीं हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पूरे देश में एक एकीकृत शिक्षा नीति की आवश्यकता है जो प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की समस्त त्रुटियों को ध्यान में रखकर बनाई जाए, जिसमें हर पहलू को ध्यान में रखा जा सके। इस दिशा में आवश्यकता है कि शिक्षा पर बजट में वृद्धि की जाए एवं राष्ट्रीय विचारकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सके।

– अरूण कुमार चौबे, शोध छात्र, इतिहास विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

शिक्षा किसी भी राष्ट्र व समाज की प्रगति का मापदंड होती है। माध्यमिक स्तर पर रोजगारोन्मुखी शिक्षा व नैतिक मूल्यपरक शिक्षा के साथ–साथ संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, तमिल, तेलगू आदि भारतीय भाषाओं को भी पाठ्यक्रम में हिस्सा बनाया जाना चाहिए, जिससे भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षा को समाज से जोड़ते हुए क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने हेतु सरकार व विश्वविद्यालयों के द्वारा ऐसे नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है जिससे शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जा सके। प्राचीन भारतीय इतिहास व विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि भाषा सम्बन्धी साहित्य पर शोध को और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए।

– ललित पाण्डेय, जेएनयू, दिल्ली

कोका-कोला के खिलाफ अभाविप ने खोला मोर्चा

वाराणसी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (अभाविप) ने कोका–कोला पर भूजल दोहन का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। अभाविप के विभाग प्रमुख विनय पाण्डेय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वाराणसी–भदोही मार्ग स्थित जंसा चौराहे पर पैदल मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोका–कोला कंपनी द्वारा अंधाधुंध जल दोहन करने से भूमिगत जल पाताल में चला गया है, जिसके चलते भीषण गर्मी में सारे क्षेत्र में पेयजल के लिए हाहाकर मच गया है।

विभाग प्रमुख विनय पाण्डेय ने कहा कि मेहदीगंज कोका–कोला की कंपनी अपनी तिजोरी भरने के लिए ग्रामीणों का पानी छीनने का काम कर रही है। जिस पानी से गरीबों की प्यास बुझती है और जो पानी खेती में काम आता है वही पानी शीतल पेय बनाने के काम आ रहा है। उन्होंने कहा कि आराजीलाइन, सेवापुरी, विद्यापीठ, हरहुआ ब्लाक के 90 प्रतिशत तक तालाब व कुंओं से पानी गायब हो चुका है, जिन जगहों पर थोड़ा पानी बचा है वह लोगों की पहुंच से दूर हो चुका है। भूगर्म विभाग ने भी इस क्षेत्र को डार्क जोन घोषित किया हुआ है।

विनय पाण्डेय ने कहा कि कंपनी 50 लाख लीटर पानी प्रतिदिन निकालती है और फैक्टरी का गंदा पानी फिर से खेतों में भेज दिया जाता है। इसके चलते क्षेत्र में बीमारी भी फैल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोका–कोला के भूजल दोहन रोकने की बजाय चेक डैम बना रही है, जिसका ग्रामीणों को कुछ लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है यदि कोका–कोला की कंपनी को बंद कर दिया जायेगा तो क्षेत्र में भूजल की स्थिति में सुधार होना शुरू हो जायेगा। अभाविप कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि वह भूजल बचाने के लिए आंदोलन करते रहेंगे।

कश्मीर घाटी में खेल

✍विवेक सिन्हा

उबाल मारती हुई अंतर्धारा को यदि नियंत्रित नहीं किया जाए तो एक प्रलंयकारी विनाश का कारण बनती है। इसी प्रकार का एक संघर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर में देखने को मिला। टी–20 क्रिकेट मैच में भारत की हार के बाद कुछ छात्रों के बीच हुई मामूली झड़प जम्मू–कश्मीर की राजधानी में युद्ध का रूप में ले चुकी है और इसके पीछे अलगाववादी ताकतों की भूमिका प्रमुख रही। मामला 31 मार्च को उपजा जब वेस्टइण्डीज के बल्लेबाज लिंड्से सिमन्स ने आखिरी ओवर में छक्का मारकर भारत को रोमांचक सेमिफाइनल में पराजित किया।

भारतीय टीम के मैच में हारने के बाद भारतीय टीम के प्रशंसकों के खेमे में एक ओर उदासी छा गई थी वहीं दूसरी तरफ 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' 'हिन्दुस्तान मुर्दाबाद' जैसे शर्मनाक नारे कुछ कश्मीरी छात्रों की तरफ से लगाए जा रहे थे और भारतीय टीम की हार का जश्न मनाया जा रहा था।

एनआईटी के छात्रों के अनुसार इन छात्रों द्वारा किया गया यह कृत्य गैर कश्मीरी छात्रों को भड़काने के लिए था। क्योंकि नारेबाजी के साथ की जा रही आतिशबाजी और हुड़दंगई अपने चरम पर थी तथा गालियों के साथ हॉस्टल की दीवारों पर पत्थर मारकर पाकिस्तान जिन्दाबाद चिल्ला रहे थे।

उस मौके पर उपस्थित एनआईटी के सुरक्षाकर्मी मूकदर्शक बन यह दृश्य देख रहे थे और बाहरी तत्वों को आने से भी रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे।

प्रायः यह देखा जाता है कि छात्रों के बीच की असहमति हिंसा में बदल जाती है परंतु प्रशासन की मदद से स्थिति को नियंत्रित किया जाता रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्यों कश्मीरी अलगाववादी बाहरी छात्रों को निशाना बना रहे हैं और कॉलेज प्रशासन क्यों गैर कश्मीरी छात्रों को हतोत्साहित करने पर तुला है।

खैर, तर्क यह है कि अलगाववादी आंदोलन वास्तव में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की अभिव्यक्ति है। परंतु यह तर्क सही नहीं लगता क्योंकि कश्मीरी भाषी मुसलमानों का सिर्फ एक समुदाय भारत की बजाय पाकिस्तान को समर्थन देता है। उनका प्रमुख लक्ष्य इस्लाम को राजनैतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर अपनी राजनीतिक महत्वाकाक्षांओं को पूरा करना है। यह सत्य है कि एनआईटी कैम्पस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्लाम का प्रयोग कर रहे हैं।

बाहरी छात्रों (गैर कश्मीरी छात्र) की मदद के लिए प्रशासन ने भी कोई प्रयास नहीं किया और ना ही कॉलेज प्रशासन ने। कॉलेज द्वारा स्थिति को नियंत्रण से इंकार करने के बाद हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने शांतिपूर्वक एकत्रित होकर और 'भारत माता की जय' नारा लगाते हुए तिरंगा लहराया। तिरंगा लहराये जाने के बाद हॉस्टल के छात्रों पर बेवजह लाठी चार्ज किया गया। तब से बाहरी छात्र जो कि एनआईटी हॉस्टल में रहते हैं, को परेशानियों (दैनिक उत्पीड़न) का सामना करना पड़ रहा है। शांतिपूर्वक इकट्ठा होने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया।

ये घटनाऐं अलगाववादियों की करतूत है जिनको कि संस्थान में समर्थक मिल गये हैं। तथा गहरे विश्लेषण के पश्चात कुछ रोचक अंतर्दृष्टि सामने आयी है।

जम्मू एवं कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन शून्य पर आ गई है। राज्य के जम्मू संभाग में अलगाववादी समर्थक का आधार सुन्नी मुसलमानों की संख्या भी तेज गति से कम हो रही है। अन्य संप्रदायों जैसे शिया मुसलमान, बक्करवाल, गुर्जर, पहाड़ी तथा अहमदीयों ने अलगाववादी विचारधारा को पूरी तरह से नकार

दिया है। वास्तव में अलगाववादियों का अस्तित्व संकट में है और इसलिए वे खबरों में बने रहने के लिए कोई अवसर नहीं चूक रहे हैं। 2 अप्रैल को अलगाववादी ने सैयद अली गिलानी ने ट्वीट किया, "भारतीयों को ध्यान में रखना चाहिए कि कश्मीर, दिल्ली या भारत के अन्य किसी राज्य जैसा नहीं है।" मीडिया का एक वर्ग इस मुद्दे को कश्मीरी मुसलमानों के मन में दबा विस्फोट कह रहे हैं और अलगाववादियों को राज्य का प्रतिनिधित्व करता है जैसे चित्रित कर रहे हैं। दुःख की बात यह है कि अभी भी अलगाववादी मुसलमानों के मन में पाकिस्तान के अस्तित्व को लेकर ऐसी भावनाऐं हैं, उन्हें लगता है कि मो. अली जिन्ना के द्वारा बनाया गया राज्य ही उनकी अंतिम सीमा है। वास्तव में यह एक भ्रम है। यहां तक कि जिन्ना ने एक बार कहा था कि "मैंने मेरे सचिव तथा टाइपराइटर की मदद से पाकिस्तान जीता।" जिन्ना ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल किया था। एक विशेष वर्ग के मुसलमान घाटी में पाकिस्तान समर्थक भावना की निरर्थकता को साकार कर रहे हैं। शब्बीर (बदला हुआ नाम) ने कहा कि "पाकिस्तान समर्थक नारे लगा कर अलगाववादी राज्य का माहौल खराब कर रहे हैं तथा इसका प्रतिकूल असर हमारी आजिविका पर पड़ रहा है। शब्बीर एक होटल का मालिक है और उनका व्यवसाय राज्य में पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या पर निर्भर करता है।

भारत सरकार को यह समझना होगा कि एनआईटी की यह घटना पहली नहीं है और न ही अंतिम। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बाहर के छात्रों की समस्या का सामाधान करने के लिए नई दिल्ली से दो सदस्यीय दल भेजा है। समकालीन स्थिति तथा सुरक्षा चिंताओं की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू–कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से स्थिति का जायजा लिया। राज्य के उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा है कि लाठी चार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों को दण्ड दिया जाएगा। साथ ही छात्रों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सच बाहर आते हुए देख गिलानी ने अपना पाला बदलने में कोई देरी नहीं की। 6 अप्रैल को अपने ट्वीट तथा फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "बाहरी छात्र यहां अध्ययन कर रहे हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।"

अंततः यह सोचना बेवकूफी होगी कि अलगाववादियों में हृदय परिवर्तन हो जायेगा। ऐसे मुद्दों कश्मीर घाटी में हलचल बनाऐ रहेंगे। अलगाववादियों से आगे सोच पाने की रणनीति तैयार करनी होगी। तथा पूर्व कारवाई करने को तैयार रहना होगा। ■

पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ संपन्न हुआ पर्यावरण महाकुंभ

पांच हजार विद्यार्थियों, प्राध्यापक और पर्यावरणविद हुए महाकुंभ में सम्मिलित

उज्जैन। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में चल रहे धार्मिक समागम सिंहस्थ कुंभ में नए–नए रंग और आकर्षण देखने को मिल रहे हैं। उज्जैन में 22 अप्रैल से शुरू हुए सिंहस्थ में शामिल होने बड़ी संख्या में देशी ही नहीं, विदेशी श्रद्धालु भी यहां पहुंच रहे हैं। यहां आने वाले श्रद्धालु महाकाल की भी एक झलक पाने को आतुर दिख रहे हैं। हर दिन महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। वहीं क्षिप्रा को अविरल, प्रवाहमान और उज्जैन को स्वच्छ बनाने के लिए सिंहस्थ कुंभ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रमुख आयाम विकासार्थ विद्यार्थी, परमार्थ निकेतन, अखिल भारतीय श्री पंच दिगम्बर अनी अखाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में एक पर्यावरण महाकुम्भ का आयोजन किया गया। प्रभु प्रेमी शिविर उजरखेड़ा में सम्पन्न हुए इस पर्यावरण महाकुंभ में पांच हजार से अधिक विद्यार्थी, प्राध्यापक, शोधार्थी, पर्यावरणविद एवं प्रबुद्धजन सम्मिलित हुए। इस दौरान, सभी ने पर्यावरण संरक्षण तथा प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए एक स्वर में 'पेड़ लगे प्यारे – हाथ उठे सारे' का संकल्प लिया।

जीवन के लिए जल एंव पर्यावरण के महत्व और लगातार घटते पीने योग्य जल की उपलब्धता पर चिंता प्रकट करते हुए आचार्य महामण्डलेश्वर अवधेशानन्द गिरि ने कहा कि सिंहस्थ की महत्ता नीर के निकट है। हमारा पूजाक्रम, अनुष्ठान की पद्धति, आचमन, तर्पण, अभिषेक, जल के बिना सम्भव नहीं है। स्वयं नारायण का अस्तित्व नीर से है, पहली कृति ब्रम्हा, पहला अवतार मीन नीर से है। पौराणिक मान्यता में ईश्वर का वास नीर में है। क्षिप्रा तालाब, वनस्पति वृक्षों से पैदा होती है। पेड़ों से मानव अस्तित्व होगा। क्षिप्रा किनारे पेड़ लगेंगे तो इसका प्रभाव गंगा जैसा होगा। नदी की केवल दो मांग हैं, निर्मल एंव अविरल.. वर्तमान समय कार्य करने का है। इसके लिए जरूरी है कि प्लास्टिक जैसे पर्यावरण विरोधी तत्वों के उपयोग पर त्वरित अंकुश लगाया जाये, जिसके लिए विकासार्थ विद्यार्थी के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आम्बेकर ने कहा कि पूरी दुनिया में पर्यावरण की रक्षा के बहुत प्रयास हो रहे है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। इसी कारण से पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है क्योंकि भारत ने सदियों से पर्यावरण को सहेज कर रखा है। पूरी दुनिया नदियों को ढ़क कर, कुओं को बंद कर, पेड़ो को काट कर बसने की परिकल्पना कर रही है। कोई शुद्ध अन्न के

लिए भटक रहा है तो कोई शुद्ध जल एवं वायु के लिए भटक रहा है। कुछ नहीं बदला बस इंसान की बुद्धि बदल गई। संतों से मिला ज्ञान, सानिध्य से जीवन बदलता है। एसएफडी ने नर्मदा अध्ययन यात्रा पूर्ण श्रद्धा से की थी, ये अभियान आज आंदोलन बन गया है। कुछ लोग भगवान और देश पर प्रश्न चिन्ह लगाकर नास्तिकता फैलाते हैं ऐसे ही लोग देश का बुरा सोचते हैं।

इस अवसर पर मुनि श्री चिदानंद जी ने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए पोलोथीन का उपयोग नही करने, नदियों को प्रदूषित नहीं करने एवं प्रदूषण को रोकने, नदियों के किनारों पर पौधे लगाने, स्वच्छ रखने एवं इस अभियान में दस-दस व्यक्तियों को जोड़ने का आव्हान करते हुए। तीन दिन में क्षिप्रा के 12 किमी के किनारे को जलदायी, फलदायी, औषधिदायी बनाने हेतु वृहद वृक्षारोपण करने का संकल्प दिलाया।

कार्यक्रम में अ.भा. श्री पंच दिगम्बर अनि अखाड़ा सचिव शिवशंकरदास जी महाराज, अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत, साध्वी भगवती सरस्वती, सुलभ स्वच्छता एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक डॉ विंदेश्वर पाठक, अफ्रीका में भारत के राजदूत रहे दिपक वोहरा, अखिल भारतीय आयाम प्रमुख नागराज रेड्डी, एसएफडी राष्ट्रीय संयोजक सचिन दवे उपस्थित रहे।

पारित प्रस्ताव

इस अवसर पर एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें राष्ट्र के धर्म तंत्र सनातन संस्कृति से जुडे संत समाज से सात प्रमुख विषयों को लेकर निवेदन किया गया।

- ***भारतीय सन्त समाज देश की युवा शक्ति को राष्ट्र-धर्म का बोध कराएं और लोक महत्व के इस भाव का समुचित प्रचार प्रसार करें।***
- ***राष्ट्र के समग्र व सतत विकास के मूल में धर्म केन्द्रित हो।***
- ***जल की महत्ता, जल की शुद्धि, जल संरक्षण तथा संवर्द्धन के महाकार्य में सन्त समाज प्रमुख भूमिका निभाएं।***
- ***सन्त समाज पर्यावरण संरक्षण, नदियों को निर्मल, सजल व अविरल बनाने तथा वन-सम्पदा को बढ़ाने के कार्य में देशवासियों को दिशा दें।***
- ***नारी सशक्तिकरण पर हमारे सन्त विशेष ध्यान दें ताकि भारतीय समाज कन्या भ्रूण हत्या तथा नारी स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग हो सकें।***
- ***स्वस्थ राष्ट्र-समुन्नत राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए सन्तजन योग विज्ञान के समुचित प्रचार-प्रसार पर ध्यान दें और इस कार्य को अपने मूल चिन्तन व क्रियान्वयन का केन्द्र बनायें।***
- ***उज्जैन महाकुंभ के समापन के उपरान्त 'स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत' की हमारे ऋषियों की परिकल्पना पूरे देश में आकार ले। इस पर हमारा सन्त समाज ध्यान दे और भारत की लोकसेवी संस्थाओं, विशेष रूप से युवाओं का मार्गदर्शन करें, सहयोग प्रदान करें।*** ■

अभाविप का मोबाइल ऐप
डाउनलोड
करने की लिंक आपको
ABVP के
अधिकारिक अकाउंट
http://www.facebook.com/ABVPVOICE
https://twitter.com/abvpcentral
पर और वेबसाइट
www.abvp.org
पर भी उपलब्ध रहेगी।

करियर

कलम और कैमरा की कवायद

✍अवनीश सिंह राजपूत

किसी भी राष्ट्र के विकास में पत्रकारिता एक अहम भूमिका निभाती है। पत्रकारिता ही वह साधन है, जिसके माध्यम से हमें समाज की दैनिक घटनाओं के बारे में सूचना प्राप्त होती है। वास्तव में पत्रकारिता का उद्देश्य जनता को सूचना देना, समझाना, शिक्षा देना और उन्हें प्रबुद्ध करना है। लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहे जाने वाला पत्रकारिता जगत एक बेहतर करियर विकल्प हो सकता है, बशर्ते उसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने का संकल्प लेने का साहस हो। समाचार पत्र या पत्रिकाओं की दुनिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संसार, रेडियो की आवाज का जादू हो या फिर वेब पत्रकारिता का जाल, सभी उत्साही व सजग कर्मयोगियों को अपने–अपने तरीके से एक मंच दे रहे हैं। यह सत्य है कि इस क्षेत्र में पत्रकारों के लिए अवसर अनंत है। किंतु समय के साथ यह कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि नया विश्व, इस कहावत को चरितार्थ कर रहा है कि "कलम और कैमरा तलवार से कहीं अधिक प्रभावशाली है।" अब घटनाओं की मात्र साधारण रिपोर्ट देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि रिपोर्टिंग में अधिक विशेषज्ञता और व्यावसायिकता होना आवश्यक है। नई–नई तकनीकों के कारण अब पत्रकारिता के कई प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहे हैं। प्रिंट, रेडियो और टीवी के बाद पत्रकारिता का भविष्य वेब पर आ गया है। अगर आप की दिलचस्पी समाचार, दुनिया में घट रही घटनाओं और लिखने में है तो आप इस क्षेत्र में आ सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता

पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं अथवा स्नातकोत्तर पाठयक्रम के लिए पत्रकारिता में स्नातक होना चाहिए। कुछ संस्थानों में पत्रकारिता में एक वर्षीय प्रमाण–पत्र पाठयक्रम संचालित किए जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए पत्रकारिता और जन संचार में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि जरूरी है। इसके बावजूद विशेष प्रशिक्षण से इस क्षेत्र में बेहतर अवसर बनाए जा सकते हैं। अगर आप स्नातक के बाद पत्रकारिता की पढ़ाई करना चाहते हैं तो यह आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। स्नातक के बाद जन संचार और जनसंपर्क में, स्नातकोत्तर किया जा सकता है। वहीं, वहीं, स्नातकोत्तर करने के बाद आप सीधे पी.एच.डी. या एम. फील. भी कर सकते हैं।

कौन–कौन से हैं पाठ्यक्रम

जनसंचार में कई तरह के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। आप चाहें तो डिग्री या फिर डिप्लोमा कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के हिसाब से शैक्षिक योग्यता भी अलग–अलग निर्धारित है, लेकिन अधिकतर संस्थान न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक ही मांगते हैं। इनमें मुख्य रूप से जनसंचार में स्नातक, प्रसारण पत्रकारिता से स्नातकोत्तर, विकासात्मक पत्रकारिता, जनसंपर्क एवं संचार तथा संचार माध्यम के जरिए भी स्नातक व स्नातकोत्तर की उपाधि ली जा सकती है। यहां इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अध्ययन के लिए उस संस्थान का चयन करें, जहां आधुनिक तरीकों से प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण ही इस क्षेत्र में सफलता का मार्ग तय करता है। कुछ संस्थान ऑनलाइन पत्रकारिता के पाठ्यक्रम अलग से भी कराते हैं।

पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए प्रमुख संस्थानः

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता व संचार विश्वविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, काशी विद्यापीठ, वाराणसी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, मास मीडिया रिसर्च सेंटर (जामिया मिलिया इस्लामिया),

जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन, गुरू जंभेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में पत्रकारिता का पाठ्यक्रम संचालित होते हैं।

पत्रकारिता पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण क्षेत्र –

प्रिंट मीडिया:

प्रिंट पत्रकारिता समाचार पत्रों पत्रिकाओं तथा दैनिक पत्रों के लिए समाचारों को एकत्र करने एवं उनके सम्पादन से संबद्ध हैं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, वे बड़ी हों या छोटी, हमेशा विश्वभर में समाचारों तथा सूचना का मुख्य स्रोत रही हैं और लाखों व्यक्ति उन्हें प्रतिदिन पढ़ते हैं। कई वर्षों से प्रिंट पत्रकारिता बड़े परिवर्तन की साक्षी रही है। आज समाचार–पत्र एवं पत्रिकाएं विविध विशेषज्ञतापूर्ण वर्गों जैसे राजनीतिक घटनाओं व्यवसाय समाचारों, सिनेमा, खेल, स्वास्थ्य तथा कई अन्य विषयों पर समाचार प्रकाशित करते हैं, जिनके लिए व्यावसायिक रूप से योग्य पत्रकारों की मांग होती है। प्रिंट पत्रकारिता में कोई भी व्यक्ति सम्पादक, संवाददाता आदि के रूप में कार्य कर सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया:

इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म पत्रकारिता को अक्षरों की दुनिया से निकालकर विजुअल की दुनिया में ले आया। इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता का विशेष रूप से प्रसारण के माध्यम से जन–समुदाय पर पर्याप्त प्रभाव है। दूरदर्शन, रेडियो, श्रव्य, दृश्य (ऑडियो, वीडियो) और वेब जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दूर –दराज के स्थानों में समाचार, मनोरंजन एवं सूचनाएं पहुंचाने का कार्य किया है। वेब में, कुशल व्यक्तियों को वेब समाचार पत्रों (जो केवल वेब की पूर्ति करते हैं और इनमें प्रिंट संस्करण नहीं होते और लोक प्रिय समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को जिनके अपने वेब संस्करण होते हैं, साइट रखनी होती है। इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता में कोई भी व्यक्ति रिपोर्टर, लेखक, सम्पादक, अनुसंधानकर्ता, संवाददाता और एंकर बन सकता है।

सोशल मीडिया:

युवाओं की पहुंच में हर वक्त रहने वाले सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तेजी से बढ़ा है, उसी तेजी से इसके विशेषज्ञों की मांग भी बढ़ रही है। कई ऐसे न करियर विकसित हो गए हैं, जिनसे बड़े स्तर पर लोग अभी भी अनजान हैं। आज अधिकांश ब्राडों ने सामाजिक नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रखी है, क्योंकि यह संस्थान की ऑन–लाइन मार्केटिंग और संचार रणनीति का एक हिस्सा होती है। ऐसे में उन युवाओं की मांग बढ़ गई है, जो आभासी दुनिया में उनकी जोरदार ब्रांडिंग कर सकें, लोगों से सही संचार स्थापित कर सकें। सोशल मीडिया में विशेषज्ञता रखने वाले कर्मियों के लिए गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन व ट्विटर जैसे क्षेत्र में काम करने के अच्छे मौके हैं।

वेब पत्रकारिता:

पत्रकारिता के इस प्रारूप में वाचक, आगंतुकों को प्रतिक्रिया की सुविधा दी, यानी आप न्यूज मेकर से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। स्मार्ट फोन के आ जाने से यह दिनप्रतिदिन आगे बढ़ रही है। पत्रकारिता के भविष्य के रूप में इस माध्यम को स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही आज लगभग सभी प्रमुख मीडिया हाउस अपने वेब पोर्टल चला रहे हैं, जहां

सामग्री निर्माता के लिए अच्छा अवसर है।

जनसंपर्क:

यह क्षेत्र पत्रकारिता से थोड़ा हटकर है, पत्रकारिता की पढ़ाई के दैरान इसे भी पढ़ाया जाता है। किसी व्यक्ति, संस्थान की छवि को लोगों की नजर में सकारात्मक रुप से प्रस्तुत करना जनसंपर्क में आता है। जनसंपर्क का पाठ्यक्रम करने के बाद व्यापार घरानों, राजनीतिक हस्तियों और संस्थानों के लिए काम किया जाता है।

विज्ञापन :

किसी उत्पाद, विचार के संचार के किसी प्रभावशाली माध्यम से ब्रांड निर्माण की प्रक्रिया को विज्ञापन कहते है। लोगों की सोच को अपने पक्ष में करने के लिए व्यावसायिक घराने, राजनीतिक संगठन और सामाजिक संस्थानों द्वारा इसका बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है।

जरुरी योग्यता:

पत्रकारिता के क्षेत्र में भविष्य बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका मानसिक रूप से मजबूत होना यानी किसी भी परिस्थिति में खुद पर विश्वास करके काम पर ध्यान देना। वहीं, पत्रकार होने के लिए बेहतरीन संचार कौशल के साथ समाचारों से खुद को रूबरू रखना पत्रकारिता का सबसे बड़ा नियम है। आपके विचारों में निष्पक्षता होनी चाहिए, कोई भी चीज कहने से पहले आपके पास उसके सबूत होने चाहिए। आपकी सोच किसी भी विषय पर एक विश्लेषक की तरह हो, यह सबसे ज्यादा जरूरी होता है।

क्या करना होगा आपको:

पत्रकार के रूप में आपको फील्ड और डेस्क दोनों पर काम करना पड़ सकता है। फील्ड वर्क में संवाददाता और शोध विभाग का काम होता है। फील्ड वर्क के काम में वे लोग ज्यादा अच्छा कर सकते हैं जिन्हें समाज की समझ है और संपर्क सूत्र अच्छे हैं। एक रिपोर्टर का प्रमुख काम होता है पत्रकार वार्ता में जाना, साक्षात्कार लेना, किसी घटना की जानकारी इकट्ठा करना। अगर आपकी दिलचस्पी फोटोग्राफी में है तो आपको फील्ड में कैमरामैन का काम मिल सकता है। कैमरामैन का काम सिर्फ फोटो खींचना नहीं होता है बल्कि ऐसे फोटो लाना होता है जो न्यूज के साथ मिल सके। वहीं, डेस्क पर समाचार लेखन, संपादन का काम मिलता है। इसके लिए आपके पास भाषा ज्ञान होना आवश्यक है।

नौकरी के अवसर:

पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद आपको समाचार एजेंसी, समाचार वेबसाइट, प्रोडक्शन हाउस, प्राइवेट और सरकारी समाचार चैनल, प्रसार भारती, प्रसारण कार्य, फिल्म निर्माण में रोजगार से अवसर मिलते हैं। आप चाहें तो फ्रीलान्सिग भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यह क्षेत्र विज्ञापन एजेन्सी, जनसंपर्क के साथ ही सामाजिक माध्यमों में भी एक अच्छा अवसर उपलब्ध कराता है। ■

प्रिय मित्रों,

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का मई 2016 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों तथा खबरों का संकलन किया गया है। आशा है यह अंक आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा।

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव एवं विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई–मेल पर अवश्य भेजें।

"छात्रशक्ति भवन"

26, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग

नई दिल्ली – 110002

फोन : 011–23216298

ई–मेल : chhatrashakti.abvp@gmail.com

वेबसाईट : www.abvp.org

वर्तमान सत्र से लागू हो नीट: विनय बिदरे

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिला अभाविप प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा से मुलाकात करते हुए मेडिकल की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को जल्द लागू किए जाने की बात कही है। अभाविप का कहना है कि वर्तमान सत्र में नीट के लागू होने से काफी संख्या में छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सकेगा।

अभाविप प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नीट लागू करने का कार्य प्रगति पर है। इसे लागू करते समय जो व्यावहारिक समस्याएं आती हैं उन्हें एक संवेदनशील सरकार की जिम्मेदारी समझते हुए काम हो रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि पहले जो नीट परीक्षा हुई थी उसमें क्षेत्रीय भा।एं थीं। ऐसे में सीबीएसई से बात की गयी मगर जरूरी तैयारी नहीं हो सकने के कारण इसके लागू होने में विलंब हो रहा है। सरकार जल्द ही नए रास्ते तलाश लेगी।

विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय महामंत्री विनय बिदरे ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं व्यापारीकरण की वजह से हजारों विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उच्च शिक्षा में इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन की आवश्यकता वर्षों से अनुभव की जा रही है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जब देशभर में मेडिकल के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया तो उसमें सभी वर्गों के छात्रों के हित सुनिश्चित करने का लक्ष्य था। यह शिक्षा के व्यापारीकरण के खिलाफ व्यापक छात्र आंदोलनों का ही परिणाम है। प्रथम वर्ष में होने वाली समस्याओं को देखते हुए नीट–1 में बैठ चुके छात्रों को भी नीट–2 में बैठने का अवसर दिया जाना एक स्वागत योग्य कदम रहा।

अपनी मांगों में अभाविप ने साफ किया कि केवल इस वर्ष हेतु प्रदेशों में सरकारी सीटों के लिए हुई परीक्षाओं को नीट की सूची में जोड़ने को लेकर सरकार कुछ मार्ग निकाल सकती है। लेकिन निजी महाविद्यालयों की सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा, उन्हें नीट 2016 में ही अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए।

विचार महाकुंभ

स्वागत... वन्दन... अभिनन्दन...

अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ

निनोरा, उज्जैन, मध्यप्रदेश

समापन समारोह

'सिंहस्थ 2016 के सार्वभौम अमृत-संदेश' का विमोचन

14 मई 2016 को सुबह 11.30 बजे

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

माननीय श्री नरेन्द्र मोदी

भारत के प्रधानमंत्री के

मुख्य आतिथ्य

एवं

महामहिम श्री मैत्रीपाल सिरिसेना
राष्ट्रपति, श्रीलंका

महामहिम श्री मैत्रीपाल सिरिसेना

श्रीलंका के राष्ट्रपति के

विशेष आतिथ्य में

सम्पन्न होगा।

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

सिंहस्थ की विचार मंथन परंपरा को पुनर्जीवित करता उज्जैन, मध्यप्रदेश

RNI No. 32464/78

मजबूत अधोसंरचना
विकसित छत्तीसगढ़

विकास का पर्याय बनी सड़कें...

- बारह वर्षों में 59136 कि.मी. सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया गया।
- 852 वृहद, 337 मध्यम पुल और 23206 पुलियों का निर्माण किया गया।
- 15 रेल्वे ओव्हर ब्रिज तथा अण्डर ब्रिज का निर्माण
- 15 बायपास मार्गों का निर्माण पूर्ण।
- एडीबी अन्तर्गत 1005 कि.मी. के 18 मार्ग पूर्ण
- नाबार्ड योजना अन्तर्गत 459 सड़कें और 174 पुल-पुलियों का निर्माण
- कारीडोर योजना अन्तर्गत 2230 कि.मी. की 6 मार्गों का निर्माण पूर्ण।
- एल.डब्ल्यू.ई. योजना के अन्तर्गत 2905 करोड़ की लागत से 2021 किलोमीटर की 19 सड़कों का कार्य पूर्ण, 21 कार्य प्रगति पर।